

02/2012



सप्रू हाउस लेख



भारत की लुक ईस्ट पालिसी के
परिप्रेक्ष्य में भारत-वियतनाम संबंध

जुआन विन्ह

अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड़,
नई दिल्ली-110001

भारत की लुक ईस्ट पालिसी के परिप्रेक्ष्य में भारत-वियतनाम
संबंध

वो जुआन विन्ह

भारत की लुक ईस्ट पालिसी के परिप्रेक्ष्य में भारत-वियतनाम संबंध

काँपीराइट © अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय
परिषद ISBN : 978-81-926825-4-9

सभी अधिकार संरक्षित हैं। इस प्रकाशन के किसी भी भाग को काँपीराइट मालिक से अनुमति के बगैर पुनरुत्पादित, पुनःप्राप्ति प्रणाली में भंडारित, अथवा किसी भी प्ररूप में चाहे इलैक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोकाँपी से रिकार्डिंग अथवा अन्यथा, रूपांतरित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में व्यक्त किये गये तथ्य एवं मतों की जिम्मेदारी पूर्णतया लेखक के पास सुरक्षित है तथा उसका विवेचन आवश्यक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली के विचारों को व्यक्त नहीं करती है।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय
परिषद

सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड़, नई
दिल्ली- 110 001, भारत

Tel. : +91-11-23317242, Fax: +91-11-23322710

www.icwa.in

विषयवस्तु

1	परिचय	5
2	भारत की लुक-ईस्ट पालिसी -वियतनाम के दृष्टिकोण से एक व्यक्तिगत परिदृश्य	
	एलईपी का गठन एवं विकास	6
	एलईपी का उद्देश्य	13
	एलईपी के दृष्टिकोण	18
3	वियतनाम-भारत संबंध	25
	वियतनाम की भूमिका-भारतीय दृष्टिकोण भारत की भूमिका	25
	राजनीतिक और रणनीतिक संबंध-पौराणिक मित्रता से रणनीतिक साझेदारी तक	29
	आर्थिक समन्वय- - अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता	36
	मानव विकास समन्वय - एक सफल मित्र	41
4	संभावनाएं और संस्तुतियां	43
	रणनीतिक और राजनीतिक पहलू:	43
	आर्थिक समन्वय	45

	मानव विकास	46
5	निष्कर्ष	47
6	समाप्ति टिप्पणियां	48

भारत की लुक ईस्ट पालिसी के परिप्रेक्ष्य में भारत-वियतनाम संबंध

परिचय

भारत ने 1991 में अपने आर्थिक सुधार और लुक ईस्ट पॉलिसी (एलईपी) को क्रमागतरूप से प्रारंभ किया। एलईपी 'वह आगे बढ़ने की प्रेरणा बन गया जो भारत को भू-राजनीतिक विवशता से आगे ले जा सकता था और दक्षिण एशियाई संदर्भों को जीतने और उभरती मुख्य क्षेत्रीय शक्तियों के मध्य स्वयं को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थान देने और प्रमुख बनने में सक्षम बना सकता था'। वियतनाम-भारत संबंध पारंपरिक, दीर्घ-कालिक एवं विश्वास और आपसी समझ पर आधारित हैं। यह अपनेआप में साझा धारणाओं और हितों की पारस्परिकता के आधार पर राजनीतिक, रक्षा और आर्थिक सहयोग सहित कई क्षेत्रों को समाहित करता है। दोनों देशों की उपलब्धियां भारत की एलईपी और वियतनाम की 'एक मिनट रुकिए' नीति अथवा नवीकरण का परिणाम है।

यह लेख भारत के एलईपी के प्रति वियतनाम के दृष्टिकोण को उजागर करने का प्रयास करता है और राजनीतिक और राजनीतिक

आयामों के क्षेत्र में भारत-वियतनाम संबंधों , आर्थिक (व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई) सहयोग और मानव संसाधन विकास का परीक्षण करने का प्रयास करता है। यह आने वाले वर्षों में वियतनाम-भारत संबंधों की संभावनाओं की भी जाँच करता है।

भारत की लुक ईस्ट नीति - वियतनाम का एक वैयक्तिक दृष्टिकोण

यह दिलचस्प है कि 'लुक ईस्ट' या 'लुक ईस्ट पॉलिसी' वाक्यांश आधिकारिक रूप से एक भारतीय द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के 1994 में *सिंगापुर व्याख्यान* के दौरान उनके समकक्ष ली कुआन यू ने कहा कि प्रधानमंत्री 'भारत को ईस्ट की ओर, एशिया-प्रशांत की गतिशीलता की तरफ ले आये' हैं। यह भी विचारणीय बिंदु है कि एलईपी की शुरुआत राजीव गांधी की पहलों में चीन और भारत के अन्य पूर्वी देशों की ओर हुई थी। आधिकारिक दस्तावेज में 'एलईपी' वाक्यांश पहली बार *वार्षिक रिपोर्ट 1995-1996* में सामने आया था। एलईपी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया है, विशेषकर 2002 में कंबोडिया के नोम पेन्ह में आयोजित पहले आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में।

एलईपी का गठन एवं विकास

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि एलईपी शब्द का सर्वप्रथम आधिकारिक प्रयोग विदेश मंत्रालय की 1995-1996 की वार्षिक रिपोर्ट में किया गया था। विदेश मंत्रालय ने अपनी 2006-2007 की वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया था कि एलईपी का प्रारंभ 1992 में किया गया था। एलईपी के उद्भव के इस समय का उल्लेख ए.एन.राम द्वारा अपने 'इंडियाज "लुक ईस्ट पालिसी-ए पर्सपैक्टिव" (के.वी. केशवन (ईडी)., बिल्डिंग ए ग्लोबल पार्टनरशिप: फिफटी इयर्स ऑफ इंडो-जैपनीज रिलेशंस, लांशर्स बुक, नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ-78) में किया गया है। हाल ही में ललित मानसिंह ने भी महसूस किया कि 'भारत ने 1992 में ईस्ट की ओर देखा'। इसका एक आधार इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि भारत दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) का 1992 में संवाद भागीदार बना था। भारतीय शैक्षणिक क्षेत्र में हालांकि, 1991 को एलईपी के प्रारंभ के तौर पर उल्लेख किया गया है।

समुदाय के अनुसार , भारत के आर्थिक सुधार और इसका एलईपी प्रारंभ एक साथ 1991 में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि, सितंबर 2007 में थाईलैंड के चुललॉन्गकोर्न विश्वविद्यालय के सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में अपने मुख्य भाषण में, तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने तब यह कहा था कि एलईपी को 1991 में लॉन्च किया गया था जब उन्होंने कहा था: 'जब हमारी लुक ईस्ट नीति' 1991 में शुरू की गई थी, तो इसने

विश्व के प्रति हमारे परिप्रेक्ष्य में एक रणनीतिक बदलाव को चिह्नित किया। यह हमारी आर्थिक सुधार प्रक्रिया की शुरुआत के साथ मेल खाया और हमारी आर्थिक व्यस्तता को बढ़ाने के लिए एक अवसर प्रदान किया। साथ ही, इसने दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया में हमारे सभ्यतागत पड़ोसियों के साथ संबंधों के नवीनीकरण को भी प्रोत्साहित किया। तब से '1990 के दशक की शुरुआत में' का पद को एलईपी के प्रारंभ के लिए व्यापक रूप से उपयोग में लाया गया था।

भारत की एलईपी ने तीन चरणों का अनुभव किया है। पहला चरण 1990 के प्रारंभ से नवंबर 2002 में आयोजित आसियान-भारतीय सम्मेलन तक था। इस अवधि के दौरान भारत ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को यथावत रखने के प्रयास किया जो कि 1980 में कंबोडियाई मामले के कारण खराब हो गये थे। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भारत ने जापान के साथ अपने संबंधों को राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन और प्रधान मंत्री पी. वी. नरसिम्हां राव की क्रमशः 1990 और 1992 में की गई यात्राओं से सुधारने की कोशिश की थी। भारत ने चीन गणराज्य (पीआरसी) के लोगों के साथ भी अपने संबंध सुधारने के प्रयास भी किये जब राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन और प्रधान मंत्री पी. वी. नरसिम्हां राव ने 1992 और 1993 में क्रमशः वहां की यात्राएं की। भारत ने जापान और चीन के साथ कई द्विपक्षीय समझौतों पर

हस्ताक्षर किये, लेकिन 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों को मुख्य कारक के रूप में देखा गया जिसने इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों को कम कर दिया। इसलिए , जैसा कि अमर नाथ राम ने तर्क दिया था , एलईपी का 'प्रारंभ में ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया' ही रहा होगा।

भारत ने आसियान और उसके सदस्य देशों से कई फलदायी उपलब्धियाँ हासिल कीं। भारत 1992 और 1995 में क्रमशः आसियान का एक क्षेत्रीय संवाद भागीदार और पूर्ण संवाद भागीदार बन गया। 1996 में, भारत आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) में शामिल हुआ। आसियान ने भारत के परमाणु परीक्षणों के खिलाफ केवल प्रतीकात्मक आपत्ति उठाई थी। अपनी एलईपी के क्षेत्र को विस्तारित करने के भारत के प्रस्ताव को तब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब उसका आसियान+3 (आसियान के साथ जापान, पीआरसी और कोरिया गणराज्य) जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, को आसियान + 4 (जो कि जैसिक के रूप में जाना जाता है जिसमें जापान, आसियान, पीआरसी, भारत और कोरिया गणराज्य भी शामिल हैं) में बदलना वास्तविक नहीं हो पाया। भारत ने सिंगापुर और वियतनाम जैसे कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ कुछ रक्षा समझौते भी किए।

आर्थिक मोर्चे पर, भारत ने कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में

व्यापार और निवेश के अवसरों पर संयुक्त सेमिनार आयोजित करके आर्थिक सहयोग की मांग शुरू की। सिंगापुर व्यापार और विकास बोर्ड तथा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा 1991में सिंगापुर में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था और दो अन्य सम्मेलनों का आयोजन 1995 में फिक्की / एसोचैम द्वारा कुआलालंपुर में किया गया था।

2002 में आयोजित पहली आसियान-भारत शिखर वार्ता ने एलईपी के दूसरे चरण के प्रारंभ को चिन्हित किया था जब तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने सिंगापुर के रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन संस्थान में अगस्त 2003 में दिये गये अपने भाषण में कहा कि: 'पिछले नवंबर में नोम फोम में पहले भारत-आसियान सम्मेलन के आयोजन के साथ, हम प्रभावशाली ढंग से 'लुक ईस्ट', पालिसी' के हमारे दूसरे चरण ' में प्रवेश कर गये हैं। इसे एलईपी की विषय-वस्तु और क्षेत्र दोनों के विस्तारित चरण के रूप में देखा जा सकता है। इस नीति का क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के लिए ही बाध्य नहीं था, यह 'धीरे-धीरे सुदूर पूर्वी और प्रशांत क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विकसित हुआ, और इसने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया , ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, पापुआ न्यू गिनी और प्रशांत द्वीप के देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों को सुगम बनाया ', जहां भारत के पास न केवल एक गहरा 'भौगोलिक पदचिह्न' है..... बल्कि यहां यह स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र

के एक अभिन्न अंग के रूप में भी स्थापित है”।

पहले चरण की तुलना में, एलईपी की विषय-वस्तु को भी विस्तारित किया गया था जैसा कि 2003 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने भाषण में भारतीय विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा कहा गया था कि: ‘(एलईपी का दूसरा पहलू)’ चरण एक में आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान देने से हटकर चरण दो में व्यापक कार्यसूची तैयार करना है जिसमें सुरक्षा सहयोग शामिल है , जिसमें समुद्री लेन और पूलिंग संसाधनों की आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में रक्षा करना शामिल है। 1990 के दशक के आरंभ में आसियान देशों के साथ भारत ने जो सैन्य संपर्क और संयुक्त अभ्यास शुरू किए थे, वे अब पूर्ण रूप से रक्षा सहयोग में विस्तृत हो रहे हैं। भारत ने चुपचाप दक्षिण पूर्व एशिया में बंदरगाहों तक नियमित पहुंच के लिए समझौते करना प्रारंभ कर दिया है। भारत के रक्षा संपर्क जापान, दक्षिण कोरिया और चीन को शामिल करने के लिए विस्तृत हो चुके हैं। भारत इससे पहले कभी भी एशिया में इस तरह की बहु-दिशात्मक रक्षा कूटनीति में शामिल नहीं हुआ। चूंकि वार्षिक आसियान प्लस इंडिया शिखर सम्मेलन की बैठक 2002 में निर्धारित की गई थी, इसलिए भारत पूर्वी एशिया में एक हितधारक बन गया है क्योंकि आसियान प्लस एक (आसियान+1) के क्षेत्र में पीआरसी, जापान और कोरिया गणराज्य के साथ भारत का एक निश्चित स्थान है।

भारत ने 2003 में असैन्य संधि और सहयोग (टीएसी) और आसियान-भारत संयुक्त सहयोग के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। 2005 में संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन (ईएएस) में भारत की भागीदारी को एलईपी के अपने दूसरे चरण में महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा सकता है। शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए, भारत के पास पूर्वी एशिया के राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच था। इस चरण में भारत ने जापान, चीन और वियतनाम के साथ रणनीतिक साझेदारी भी स्थापित की।

आर्थिक क्षेत्र में भारत ने पूर्वी एशिया में अपने महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारों के साथ आसियान और एक पैन-एशिया मुक्त व्यापार समझौता सहित व्यापार समझौते के प्रारूपों के निर्माण की पहल की शुरुआत की। 2002 में, कंबोडिया में भारत के प्रधानमंत्री ए.बी. वाजपेयी ने 10 वर्षों के भीतर भारत-आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र का प्रस्ताव रखा। एक द्विपक्षीय भारत-थाईलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत भी शुरू की गई। वाजपेयी ने आगे 2003 में बाली, इंडोनेशिया में आयोजित दूसरे आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में एक एशियाई आर्थिक समुदाय की शुरुआत की। भारत ने आसियान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ (सीईसीए) स्थापित करने के अपने प्रयासों और और जापान तथा

कोरिया गणराज्य के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों (सीईपीए) के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के प्रयासों को जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप, भारत ने 2003 में थाईलैंड के साथ एफटीए पर एक ढांचागत समझौता संपादित किया और 2009 में आसियान के साथ वस्तु व्यापार पर एक एफटीए संपादित किया। इसने 2003 में आसियान के साथ सीईसीए पर एक ढांचागत समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक द्विपक्षीय भारत-सिंगापुर सीईसीए पर 2005 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत-कोरिया सीईपीए अगस्त 2009 में संपन्न हुआ था।

एलईपी के तीसरे चरण को भारत द्वारा पूर्वी एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संपर्क के सार्वजनिक दावे के रूप में चिह्नित किया गया था। यह कदम भारतीय रक्षा मंत्री ए.के.एंटीनी के अक्टूबर 2010 में हनोई में पहली आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम+) में दिए गए भाषण से शुरू हुआ। इससे पहले कभी भी किसी भारतीय अधिकारी ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से समर्थन और प्रतिबद्धता को दिखाया नहीं था। एंटीनी ने अपने भाषण में जोर दिया कि:

“ आज के विश्व में संचार की समुद्री लाइनों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। समुद्री लेनो को खुला, सुरक्षित और

दिकचालन, व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्तियों से मुक्त रखना सभी देशों का सार्वजनिक हित है। पाइरेसी वैश्विक समुदाय के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है जैसा कि हमने अदन की खाड़ी और उससे लगे हुए क्षेत्र में देखा है। भारतीय नौसेना सक्रिय रूप से दो साल से अधिक समय से अदन की खाड़ी में एंटी-पायरेसी पैट्रोलिंग और एस्कॉर्ट ऑपरेशन प्रदान करने में लगी हुई है। भारत पाइरेसी का समाधान करने के प्रयासों में अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। समुद्री लेन की सुरक्षा एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि अब वैश्विक आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक है। एशिया में शिप (आरसीएएपी) और मलक्का जलडमरूमध्य तंत्र के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती के समझौते पर, क्षेत्रीय सहयोग समझौते के माध्यम से, हम इस क्षेत्र में नेविगेशन की सुरक्षा में सुधार करने के लिए क्षेत्र के अन्य देशों के साथ साझेदारी कर रहे हैं। समुद्री सुरक्षा पर सहकारी दृष्टिकोण इस क्षेत्र के लिए समग्र रूप से लाभ प्रदान करेगा”।

यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि चीन के दक्षिण चीन सागर/पूर्वी सागर (एससीएस/ईएस) पर संपूर्ण संप्रभुता के दावे और

जब अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि इस समुद्र में अमेरिका का राष्ट्रीय हित है, के बाद भारत का दृढ़ रवैया सामने आया। जो भी कारण हो, 'नई दिल्ली उन मुद्दों की सीमा का विस्तार कर रही है, जिन पर वह पूर्वी एशियाई देशों को व्यापार से लेकर व्यापक आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दों पर ले जाता है, जो कि "भारत की दृष्टि में एक रणनीतिक बदलाव " का प्रतिनिधित्व करता है, और जो इस समझ पर आधारित था कि पूर्वी एशिया के घटनाक्रम भारत के सुरक्षा और विकास के प्रत्यक्ष परिणाम हैं'। तब से, भारतीय नेताओं के भाषणों में क्षेत्र से संबंधित मुद्दों में एशिया-प्रशांत, एससीएस/ईएस विवाद मुख्य बिंदुओं में से एक संवेदनशील मुद्दा नहीं है। इस मामले में भारत की रुचि को स्पष्ट रूप से तब दिखी जब भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और जापान के प्रधान मंत्री योशिहिको नोडा व अन्य के साथ पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2011 में एससीएस/ईएस विवाद को चीन की आपत्ति के बीच उठाया।

इस चरण में , भारत ने पूर्वी एशिया में कई मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत की। इसने जापान और सीईसीए के साथ क्रमशः 2010 और 2011 में मलेशिया के साथ सीईपीए का निष्पादन किया। भारत और इंडोनेशिया ने अक्टूबर 2011 में द्विपक्षीय सीईसीए पर बातचीत करनी प्रारंभ की थी। जनवरी

2012 में भारत और थाईलैंड ने व्यापक द्विपक्षीय बाजार खोलने के समझौते के लिए बातचीत में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। 2010 में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में, भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने सेवाओं और निवेश में प्रारंभिक भारत-आसियान एफटीए के लिए दबाव डाला था।

भारत ने कभी-कभी विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया-प्रशांत के प्रति अपनी रणनीति को लागू करने में चीन से पीछे रहने की बात कही है। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन भारत अब पूर्वी एशिया क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति में है। स्पष्ट है, भारत ने एलईपी के माध्यम से फलदायी उपलब्धियां हासिल की हैं।

एलईपी के उद्देश्य

एलईपी के किसी भी स्पष्ट उद्देश्य को भारत सरकार द्वारा अभी तक प्रचारित नहीं किया गया है। हालाँकि, नीति को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों और भारत की घरेलू राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप विकास के अपने दो दशकों में नियमित रूप से समायोजित और आगे पूरक बनाया गया है।

एलईपी के कदमों की तैनाती की वास्तविकता से, नीति के उद्देश्यों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले समूह में रणनीतिक और राजनीतिक आयाम जैसे: (1) भारत के व्यापार विनिमय और निवेश की सुविधा के लिए देशों, क्षेत्रीय सहयोग

संस्थानों और एशिया-प्रशांत में अच्छे संबंधों का निर्माण , और क्षेत्र में अपनी शक्ति की स्थापना ; और (2) इस क्षेत्र में भारत की आर्थिक और राजनीतिक प्रभावहीनता को बढ़ाता है , विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी क्षेत्रीय अखंडता और दक्षिण एशिया क्षेत्र और हिंद महासागर में हितों से दूरी और सीधे एशिया-प्रशांत में अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए शामिल हैं।

रणनीतिक और राजनीतिक गणनाएं आंशिक तौर पर चीन द्वारा दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाने व बाद में अक्साइ चिन और अरुणांचल प्रदेश राज्य में अपना संप्रभुत्व का दावा के विषय में भारत की जागरूकता के कारण उत्पन्न हुई हैं।

एशिया-प्रशांत में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के क्रम में, भारत ने दक्षिणपूर्व एशिया अथवा पूर्वी एशिया जिसके विषय में माना जाता है कि उसे आसियान के द्वारा संचालित किया जाता है के, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग से जुड़ने के प्रयास किए। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय वार्ता साझेदार बना और 1995 में इसका पूर्ण संवाद सहयोगी बना। 1996 में भारत आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) से जुड़ा, वार्ता जिसके विषय में भारत 'मानता है कि आसियान प्रचालक शक्ति है.....और विश्वास करती है कि.....आसियान में भागीदारी हमको (भारत को) आसियान से भी बाहर अन्य देशों के साथ जोड़ती है और भारत की कटिबद्धता और क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व के भारत के लक्ष्य को रेखांकित

करने में भारत को सक्षम बनाती '। 2002 में पहला आसियान-भारत वार्षिक सम्मेलन नोम पेन्ह, कंबोडिया में आयोजित हुआ। कई लोगों की नज़र में , शिखर सम्मेलन एशिया-प्रशांत में एक प्रमुख प्रचालक बनने के भारत के अनवरत प्रयासों में एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि, 'भारत आसियान के साथ शिखर-स्तरीय संबंधों के लिए 1999 से प्रयास कर रहा था, लेकिन इस प्रयास को बाधित किया जा रहा था और वह भी विशेष रूप से चीन के द्वारा'।

भारत की लुक ईस्ट पालिसी का एक महत्वपूर्ण उन्नति यह थी की भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएसएस) का संस्थापक सदस्य बन गया था। 2002 से 2006 के दौरान भारत की लुक ईस्ट पालिसी के जिम्मेदार रहे विदेश मंत्रालय के पूर्व विशेष सचिव (ईआर) और सचिव (पूर्व), राजीव सिकरी के शब्दों में ईएसएस में भारत की सदस्यता ने भारत और पूर्वी एशिया के मध्य के अंतर को पाट दिया यदि ईएसएस एशियाई समुदाय निर्माण के लिए एक विश्वसनीय रूपरेखा का प्रबंध में करने में सफल हो पाया तो, एशिया विकास और प्रभुत्व के एक नए और स्वतंत्र स्तंभ के रूप में उभर सकता है, जिससे कि एशिया के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी समीकरण बदल जाएंगे। यदि, 21वीं सदी को वास्तव में एक "एशियाई" सदी होना है तो ऐसा बिना भारत के इस प्रयास में मुख्य केंद्र में रहे बगैर नहीं हो सकता है '। एशिया-प्रशांत में भारत की राजनीतिक प्रतिष्ठा को भारतीय रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी द्वारा अपने

पहले *आसियान रक्षा* मंत्रियों की अक्टूबर, 2010 में वियतनाम में आयोजित बैठक (एडीएमएम+) में चिन्हित किया गया था क्योंकि एडीएमएम + एक मजबूत, प्रभावी, खुला और समावेशी क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना का एक प्रमुख घटक है जो (हमारी) आम सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए एडीएमएम को आठ "से अधिक देशों" के साथ सहयोग करने में सक्षम करेगा तथा एडीएमएम प्लस गतिविधियों में भारत को एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में देखा जाता है।"

दूसरे समूह में आर्थिक , विशेष रूप से व्यापार और सामाजिक गणनाएं शामिल हैं। पहली, भारत का मानना है कि पूर्वी एशिया भारत की निरंतर आर्थिक वृद्धि की कुंजी है, विशेषकर तब, जब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियाँ भारत के विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो रही हैं, और अन्य क्षेत्र बहुत धीमी गति से विकास कर रहे हैं और अधिक संरक्षणवादी बन रहे हैं'। वास्तव में, जब से 1991 में भारत ने अपना आर्थिक सुधार शुरू किया, तब से व्यापार भारत के विकास में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण कारक बन गया है। 'जीडीपी के अनुपात में भारत का दोतरफा व्यापार (माल का निर्यात और आयात) , एशियाई संकट के वर्ष , वित्त वर्ष 1997-98 में 21.2 प्रतिशत से बढ़कर , वित्त वर्ष 2007-08 में 34.7 प्रतिशत रहा '। वित्त वर्ष 2009-10 में एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार वित्त वर्ष 2003-04 में 37,912.66

मिलियन अमेरिकी डॉलर से 141,023.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के कुल व्यापार में एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2003-04 में 26.70 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2009-2010 में 30.19 प्रतिशत हो गई जबकि भारत के यूरोपीय संघ-27 और उत्तरी अमेरिका के कुल व्यापार में अनुपातिक तौर पर इसी अवधि में क्रमशः 20.84 प्रतिशत और 12.69 प्रतिशत से 15.94 प्रतिशत और 8.50 प्रतिशत की विशेष कमी आई।

दूसरा, भारत का मानना है कि एशिया-प्रशांत वैश्विक बाजार में भारत की छलांग के लिए स्प्रिंगबोर्ड हो सकता है। राजीव सीकरी ने आगे कहा कि: 'चूंकि भारत के पास प्रचालकीय अथवा वार्ता के अधीन, मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) या व्यापक आर्थिक सहयोग/भागीदारी समझौतों की सबसे बड़ी संख्या है तो यह आसियान और पूर्वी एशिया के देशों के साथ इस क्षेत्र में यह महत्व रखता है कि भविष्य में दुनिया के साथ भारत के आर्थिक संपर्क के लिए यह जारी रहेगा। हालांकि, 21वीं सदी के अंत तक दक्षिणपूर्व एशिया के साथ जापान और दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्थाओं ने भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र, विशेषकर जब भारत अपने प्रमुख व्यापार साझेदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को संपन्न करने के लिए प्रयासरत था विशेषरूप से जैसे कि अमेरिका, यूरोपीय संघ

(ईयू), खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) तथा चीन के साथ यह प्रक्रिया कठिन परिस्थितियों में थी, तो उस समय इसकी सहायता की थी। भारत के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के महत्व के लिए एक ठोस प्रमाण के रूप में भारत की तालिका 1 में निष्पादित हो चुके व्यापार समझौतों की विस्तृत सूची को एक प्रेरक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है।

तीसरा, एशिया-प्रशांत में आर्थिक साझेदार महत्वपूर्ण ढंग से भारत के अंतर्वर्ती प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में योगदान कर रहे हैं। 'भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह जीडीपी (2008) का मात्र 0.8 प्रतिशत रहै है तथाअगले 5 वर्षों (2013) में जीडीपी कम से कम 1.6 प्रतिशत बढ़ जाएगी'। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत) के आकड़ों के अनुसार जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, हांग कांग, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, थाइलैंड और फिलीपींस सहित एशिया-प्रशांत की अर्थव्यवस्थाओं ने अगस्त 1991 से सितंबर 2005 के दौरान भारत के कुल एफडीआई प्रवाहों में 15.08 प्रतिशत (4.362 बिलियन अमेरिकी डालर/28.930 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का योगदान दिया है। उसी स्रोत से सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, हांग कांग, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया और मलेशिया ने अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2010 के दौरान 18.434

अमेरिकी डालर का निवेश भारत में किया जो कि पहले के एफडीआई के 15.03 प्रतिशत आंतरिक प्रवाह था। उल्लिखित संख्याएं छोटी नहीं हैं, क्योंकि एक बहुत विशेष मामले में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश (आईएमएफ) की सूची में 123 वे नंबर पर सूचीबद्ध-मारीशस-11.313 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था (2011), अप्रैल 2000 से दिसंबर 2008 के दौरान भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 43.79 प्रतिशत है।

चौथा, एलईपी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बांग्लादेश और दक्षिणपूर्वी एशियाई मुख्य देशों के लिए रास्ते खोलने के प्रयासों के साथ भारत के उत्तर पूर्वी आठ राज्यों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना व सामाजिक-सुरक्षा को स्थापित करना भी है। उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) यह निर्धारित करती है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) की एक 'ताकत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है , एस.ई. एशिया' है तो फरवरी 2006 में अपनी 52 वीं बैठक में, परिषद ने भारत सरकार की लुक ईस्ट पालिसी के भाग के रूप में सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के मिशन मोड पर जोर दिया। क्षेत्र को एशियाई देशों एसई के साथ व्यापार का पूरा लाभ प्राप्त करने में सक्षम करने के लिए पूरी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। एनईसी ने अपनी 53 वीं बैठक में आगे जोर दिया कि 'लुक ईस्ट पालिसी में अलगाव को तोड़ने और क्षेत्र में समृद्धि लाने की क्षमता है'।

मूल रूप से , एलईपी को दिसंबर 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान व्यापार सलाहकार परिषद के विशेष नेता संवाद में अपने मुख्य भाषण में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा बताए गए दृष्टिकोण के रूप में समझा जा सकता है: 'आप में से कुछ को याद होगा कि हमारी सरकार ने 1992 में, भारत की 'लुक ईस्ट पालिसी' प्रारंभ की थी'। यह मात्र एक बाहरी आर्थिक नीति नहीं थी , यह भारत की वैश्विक दृष्टि में और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के स्थान में एक रणनीतिक बदलाव भी था और इससे भी अधिक, यह दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया में हमारे सभ्य पड़ोसियों तक पहुंचने के विषय में था। तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आगे बताया कि 'भारत की लुक ईस्ट नीति' एक आर्थिक अनिवार्यता से भी कहीं अधिक थी। यह भारत के विज्ञान और वैश्विक परिदृश्य में और शीत युद्ध के बाद से उसके स्थान में महत्वपूर्ण बदलाव था। आने वाले वर्षों में हमारा यह प्रयास होगा कि हम भारत और पूर्वी एशिया के बीच राजनीतिक, भौतिक और आर्थिक संपर्क को मजबूत करें और शांति और समृद्धि के लिए हमारी खोज के आधारों को व्यापक बनाएं।

एलईपी के दृष्टिकोण

भारत ने अपनी एलईपी को कैसे क्रियान्वित किया है ? यह स्पष्ट है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति ने कई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा,

सांस्कृतिक और ऊर्जा कूटनीति से लेकर उप-क्षेत्रीय संबंध शामिल हैं।

राजनीतिक मोर्चे पर, 1990 के दशक के प्रारंभ से भारतीय नेता अपनी पहल पर इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को पुनर्जीवित करने और आगे बढ़ाने के लिए कई पूर्वी एशियाई देशों का दौरा कर रहे थे। 1990 में, प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने मलेशिया का दौरा किया था। राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने जापान (1990) , वियतनाम और फिलीपींस (1991), और पीआरसी (1992) का दौरा किया था। जून 1991 में प्रधान मंत्री के पद पर आसीन होने के बाद, प्रधान मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने क्रमशः 1992 में जापान, 1993 में पीआरसी, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड और 1994 में सिंगापुर और वियतनाम 1995 में मलेशिया की यात्राएं की। यही कारण है कि 1994 में सिंगापुर में राव के भाषण को *“भारत और एशिया-प्रशांत: एक नये संबंध का निर्माण”* का नाम दिया गया था। बल्कि, भारत ने देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारा और आसियान के संवाद साझेदार, एआरएफ और आसियान +1 जैसे क्षेत्रों में क्रियाप्रणाली पर सहयोग में शामिल हुआ।

1999 में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन की बैठक को आयोजित करने के प्रयास में विफल होने के बाद, कई भारतीय नेताओं ने पूर्वएशियाई देशों की यात्राएं कीं। उस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने 2001 में वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान और 2002 में कंबोडिया और सिंगापुर का दौरा किया। इस संबंध में भारत का सबसे सफल प्रयास 2002 से वार्षिक आसियान-भारत

शिखर बैठक का प्रारंभ होना था। भारत ने 2003 में ईएएस का सदस्य बनने के लिए एक मापदंड, टीएसी की पुष्टि की।

आर्थिक क्षेत्र में, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण भारत के राजनयिक मिशन की प्रेरक शक्ति बन चुका है तथा एशिया-प्रशांत को देश की आर्थिक कूटनीति का मुख्य केंद्र माना गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, भारत ने पूर्वी एशिया और अन्य स्थानों पर अपने महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते प्रारंभ किए हैं। अपने क्रमिक प्रयासों के बाद, भारत को महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके कई मुक्त व्यापार समझौते इसी क्षेत्र से निष्पादित हुए हैं (तालिका 1 देखें)।

रक्षा कूटनीति जिसे कि सर्वप्रथम 1999 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आधिकारिक रूप से संदर्भित किये जाने के रूप में देखा गया, वह एलईपी की बढ़ते हुए क्रम में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बन गया। भारत की रक्षा कूटनीति में अनेक गतिविधियों जैसे कि रक्षा संवाद, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, उच्च स्तरीय दौरे और कुछ मामलों में हथियार निर्यातों को शामिल किया जाता है। इसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों पर ही तैनात किया जाता है। बल्कि, भारत की रक्षा कूटनीति 1990 से अस्तित्व में आयी। एक भारत-मलेशिया रक्षा समझौता 1993 में हस्ताक्षरित हुआ था और दूसरा भारत और वियतनाम के मध्य 1994 में

हस्ताक्षरित हुआ। भारत ने नवंबर 1992 में सभी आसियान सदस्यों को एक नौसेना अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया लेकिन यह पहल क्रियान्वित नहीं हो पाई। 2000 में तत्कालीन भारतीय रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडिस की जापान यात्रा के बाद, भारत ने पूर्वी एशिया क्षेत्र में नौसेना उपस्थिति को विस्तारित किया। भारत ने पीआरसी के साथ एक संयुक्त अभ्यास, जापानी समुद्र में अमेरिका और जापान के साथ तथा बंगाल की खाड़ी में आस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर और अमेरिका के साथ 2007 में संयुक्त नौसेना अभ्यास निष्पादित किए। भारत की मित्रता नौसैनिक यात्राओं का संचालन दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में किया गया है।

बहुपक्षीय स्तर पर, भारत 1996 में एआरएफ और 2010 में एडीएमएम + में शामिल हुआ।

तालिका 1: 2003-2011 के दौरान भारत के मुक्त व्यापार समझौते

साझेदार	हस्ताक्षरित	स्थिति
PTA		
दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार समझौता (एसएपीटीए)	अप्रैल 1993	दिसंबर 1995 से प्रभावी।

अफगानिस्तान	2003	अप्रैल 2003 से प्रभावी।
मर्कोसुर	2005	जून 2009 से प्रभावी।
चिली	2006	अगस्त 2007 से प्रभावी।
दक्षिण अफ्रीकी सीमाशुल्क संघ (एसएसीयू)	अभी नहीं	2005 में वार्ता प्रारंभ हुई।
एफटीए		
श्री लंका (आईएसएफटीए)	1998	2000 से प्रभावी।
दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (एसएफटीए)	2004	जनवरी 2006 से प्रभावी।
बीआईएमएसटीईसी-एफटीए (सरचना समझौता)	फरवरी 2004	जुलाई 2006 से प्रभावी।
आसियान (वस्तुओं का व्यापार)	2009	जनवरी 2010 से प्रभावी।
थाइलैंड (सरचना समझौता)	2003	2003 से वार्ता प्रारंभ हुई; ईएचपी का कार्यान्वयन
ईयू	अभी तक नहीं	2008 में वार्ता प्रारंभ
खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी)	अभी तक नहीं	मार्च 2006 में वार्ता प्रारंभ
सीईसी ए		
आसियान (सरचना समझौता)	2003	जनवरी 2006 से प्रभावी।

सिंगापुर	जून 2005	अगस्त 2005 से प्रभावी।
मलेशिया	फरवरी 2011	जुलाई 2011 से प्रभावी।
इंडोनेशिया	अभी तक नहीं	अक्टूबर 2011 में वार्ता प्रारंभ
सीईपी ए		
दक्षिण कोरिया	अगस्त 2009	जनवरी 2010 से प्रभावी
जापान	फरवरी 2011	अगस्त 2011 से प्रभावी।
सीईसी पीए		
मॉरीशस	अभी तक नहीं	बातचीत का पहला चरण अगस्त 2005 में आयोजित हुआ।

स्रोत: लेखक द्वारा विश्वसनीय स्रोतों से अनुपालित किया गया

भारत ने 1995 के बाद से चीन को छोड़कर एशिया-पैसिफिक में कई समुद्री देशों की नौसेनाओं की भागीदारी के साथ मिलान की रूपरेखा में द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास भी संचालित किया है।

संस्कृति भारत की कूटनीति का एक अभिन्न अंग है। यह 'संपूर्ण विश्व एक परिवार है' के विचार से जुड़ी हुई है। एलईपी में सांस्कृतिक कूटनीति को आंशिक रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्रों जैसे कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम, कोलंबो योजना की तकनीकी सहयोग योजना (टीसीएस), सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना (जीसीएसएस), मेकांग गंगा सहयोग छात्रवृत्ति योजना (जीसीसीएसएस), आईओआर-एआरसी छात्रवृत्ति योजना और बीआईएमएसटीईसी सदस्य देशों के लिए आयुष छात्रवृत्ति जैसी अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं में आंशिक रूप से प्रतिबिम्बित किया है।

हाल ही के वर्षों में, भारत ने कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम में अंग्रेजी प्रशिक्षण केंद्रों, उद्यमिता विकास केंद्रों और सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी प्रारंभ की है। इसके परिणामस्वरूप, 2009 में अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण का म्यांमार-भारत केंद्र पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए , जबकि अंग्रेजी भाषा का म्यांमार-भारत केंद्र (एमआईसीईएलटी), एक म्यांमार-भारत उद्यमिता विकास केंद्र (एमआईडीसी) और सू.त. कौशल संवर्धन का भारत-म्यांमार केंद्र (आईएमसीईआईटीएस) ये

सभी प्रचालन में हैं।

आईएआई (आसियान एकीकरण की पहल) कार्यक्रम के अंतर्गत, कंबोडिया-भारत उद्यमिता विकास केंद्र (सीआईडीसी) फरवरी, 2006 में खोला गया था और कंबोडिया-भारत अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण केंद्र (सीआईसीएलटी) अगस्त, 2007 में स्थापित किया गया था। एलआईडीसी (लाओ-भारत उद्यमिता विकास केंद्र) और एलआईसीएलटी (अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण के लिए लाओ भारतीय केंद्र) की स्थापना क्रमशः 2004 और 2007 में वियतनाम में की गई थी। भारत और इसके विभिन्न भागीदारों के बीच पिछले दो दशकों में कई द्विपक्षीय सांस्कृतिक लेन-देन हुए हैं। एक अन्य प्रगति में, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की भारत की पहल को 2007 में सेबू, फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में ईएस सदस्य देशों के नेताओं द्वारा समर्थित किया गया था।

21वीं सदी के प्रारंभ के बाद, भारत की लगातार बढ़ती ऊर्जा आपूर्ति की मांग ने ऊर्जा सुरक्षा को अपनी विदेश नीति की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक बना दिया और इसीलिए, ऊर्जा कूटनीति एलईपी का एक महत्वपूर्ण घटक बन गई। इस क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय सहयोग प्रभावी प्रतीत होता है, जबकि एशिया-प्रशांत में बहुपक्षीय ऊर्जा सहयोग के लिए कोई क्रिया-प्रणाली मौजूद नहीं है। भारत 1980 के दशक के

उत्तरार्ध से एससीएस/ईएस में वियतनाम के साथ संयुक्त अपतटीय ऊर्जा विकास परियोजनाओं में लगा हुआ है, लेकिन ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के तेल और गैस की वियतनाम के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 127 और 128 के ब्लॉक में खोज में निरंतरता की भारत की कोशिशों को चीन की आपतियों और चेतावनियों के बावजूद गति मिली है।

म्यांमार में, म्यांमार में बंगाल की खाड़ी में श्वे गैस भंडार में ए1 और ए3 के दो अपतटीय ब्लॉकों से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को हासिल करने में विफल रहने के बाद, भारत म्यांमार में अपनी ऊर्जा गणना में अधिक दृढ़निश्चयी रहा है। एक उल्लेखनीय प्रगति में, भारत की राज्य-चालित तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और उसके समकक्ष म्यांमार तेल और गैस उद्यम ने सितंबर 2007 में तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए , जिससे ओएनजीसी की विदेशी निवेश शाखा ओवीएल को राखिने तट पर तीन गहरे-पानी खोज ब्लॉकों एडी-2, एडी-3 और एडी-9 में गैस का पता लगाने की अनुमति मिली। भारत ने 'म्यांमार में चिंडविन नदी पर जल विद्युत क्षमता विकसित करने में अपनी रुचि' व्यक्त की।

इंडोनेशिया में भारत की कई बड़ी कंपनियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। स्पाइस एनर्जी , टाटा पावर , चेन्नई के सुराणा इंडस्ट्रीज और रिलायंस पावर लिमिटेड ने इंडोनेशिया में अपने संबंधित साझेदारों के साथ प्राकृतिक गैस या भारत में थर्मल ऊर्जा

को स्थानांतरित करने के लिए समझौता किया।

उप-क्षेत्रीय संपर्क एलईपी का एक महत्वपूर्ण घटक है। आसियान की प्रचालकीय शक्ति के साथ एशिया-प्रशांत में मौजूदा क्षेत्रीय तंत्रों में भाग लेने के अलावा , भारत ने उप-क्षेत्रीय संपर्क के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में अपने एकीकरण को भी बढ़ावा दिया है। 1997 में बीआईएसएसटीईसी (पाकिस्तान को छोड़कर अन्य सार्क देश) एवं चीन को छोड़कर, मेकांग-गंगा सहयोग की शुरुआत जिसमें ग्रेटर मेकांग उप-क्षेत्र (जीएमएस) के सदस्यों को भी शामिल किया गया वह एलईपी के संदर्भ में भारत के महत्वपूर्ण सहयोगी मार्ग बन गए। उप-क्षेत्रीय संपर्कों में से एक बीआईएमएसटीईसी की बात करते हुए, भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा: हम बीआईएमएसटीईसी में हमारी भागीदारी को अपनी 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के अंतर्गत एक प्रमुख तत्व के रूप में देखते हैं और भूमि अथवा समुद्र दोनों के द्वारा अपने सभी पड़ोसियों के लिए अच्छे पड़ोसी के तौर पर अंत तक साथ देने की पहल रखते हैं। पूर्वी एशिया और आसियान के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित मेक्योंग-भारत आर्थिक गलियारे जो कि 'जो प्रायद्वीप में गलियारों को , और संभवतः पूर्वी एशियाई क्षेत्र के साथ-साथ भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र को जोड़ने का प्रस्ताव करता है' यह मेक्योंग-गंगा सहयोग का एक नया घटक बन सकता है अथवा दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत के उप-

क्षेत्रीय संपर्कों एक बिलकुल नया कारक बन सकता है। हालांकि , यह स्पष्ट है कि उप-क्षेत्रीय संपर्क में एलईपी की रणनीतिक और राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक कूटनीति शामिल है।

वियतनाम-भारत संबंध

भारतीय दृष्टिकोण -वियतनाम की भूमिका

वियतनाम, एशिया-प्रशांत, एलईपी में भारत की विदेश नीति की गणना में कई रणनीतिक साझेदारियों में से एक है। भारतीयों की नजर में, “वियतनाम, दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की राजनीतिक, आर्थिक एवं रक्षा हितों को प्रोत्साहित करने में, और सिद्धांततः हमारी लुक ईस्ट पालिसी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है ”। वियतनाम दक्षिण-पूर्व एशिया में उच्च राजनीतिक स्थिरता और सात प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ एक सफल आर्थिक प्रदर्शन करने वाली संभावित क्षेत्रीय शक्ति है। वियतनाम की भू-रणनीतिक स्थिति, इसके प्रदर्शनकारी सैन्य कौशल और इसकी राष्ट्रीय इच्छा-शक्ति इसे दक्षिण-पूर्व एशिया के रणनीतिक गणना में महत्वपूर्ण स्थान देता है। आर्थिक रूप से, वियतनाम आर्थिक उदारीकरण पर अपने तनाव के साथ भारतीय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए बहुत ही आकर्षक तरजीह देता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में, वियतनाम का अपतटीय तेल भंडार भारत

को अनुसंधान और अंततः आपूर्ति के लिए अवसर प्रदान करता है। राजनीतिक और विदेश नीति के मुद्दों पर वियतनाम भारत का लगातार समर्थक रहा है , जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सुधार के लिए हमारी योजना और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए हमारी हाल ही में बोली शामिल है। द्विपक्षीय रूपरेखा में सहयोग के अलावा, दोनों देशों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर संयुक्त राष्ट्र, एनएएम और आसियान में अन्य क्रियाप्रणाली जैसे एआरएफ, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और मेकांग-गंगा सहयोग जैसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घनिष्ठ सहयोग और आपसी सहयोग बनाए रखा है।

यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि , हालांकि आक्रामक लेकिन चीन-पाकिस्तान सैन्य संबंध को रोकने के लिए भारत-वियतनाम के समझौते को देखने का इच्छुक राजनीतिक सर्कल मौजूद हैं। एनएएम टुडे, अप्रैल 2010 में अपने लेख में, पी.के. पटासनी लिखते हैं: कि रणनीतिक रूप से, दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्वी किनारे पर स्थित वियतनाम को भारत द्वारा चीन के दक्षिण के विस्तार के लिए मुख्य बाधा के रूप में देखा जाता है। इससे भी अधिक, चीन ने पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध स्थापित करके भारत को विवश करने का प्रयास किया है, नई दिल्ली रक्षा सहयोग में शामिल रहा है, और अपने प्रतिद्वंद्वी के छोटे, सैन्य पड़ोसी को सैन्य सहायता प्रदान की है।

भारत ने एलओपी में वियतनाम को क्यों अधिक महत्व दिया है? सबसे पहले तो भारत और वियतनाम के संबंध ऐतिहासिक हैं। वियतनाम-भारत के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिया था। 1954 में नये-नये आजाद हुए हुए उत्तरी वियतनाम की यात्रा करने वाले प्रथम विदेशी मंत्री भारतीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू थे। इसके बाद दोनों देशों ने तटस्थ आंदोलन की रूपरेखा में समन्वय स्थापित किया था। भारत ने वियतनाम को बाद में उसकी अमेरिका के साथ युद्ध में सहायता की थी जबकि वियतनाम ने 1971 में भारत का साथ पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में दिया था। और शीत युद्ध के दौरान भारत और वियतनाम मजबूत राजनीतिक साझेदार रहे। दूसरा, वियतनाम भारत को शक्ति संतुलन के पूर्व नीति में मुख्य कारकों में से एक के रूप में देखता है। जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ तो भारत ने जुलाई 1991 में अपने आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया और वह धीरे-धीरे क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक शक्ति बन गया। अमेरिका और रूस ने दक्षिणपूर्व एशिया में अपने सैन्य ठिकानों को हटा दिया और अचानक ही इसने क्षेत्र में 'शक्ति के अभाव' का निर्माण कर दिया।

एक भारतीय के रूप में पी.वी. नरसिम्हा राव ने 1994 में सिंगापुर में अपने भाषण में कहा था कि : 'शीत युद्ध की

समाप्ति के बाद अमेरिका के पीछे हटने के बाद संभावित शक्तियां जो ये जगह ले सकती हैं उनमें चीन और जापान के साथ भारत को भी एक संभावित शक्ति के रूप में दिखाया गया था। इसके आविर्भाव ने भारत को एशिया-प्रशांत में एक महत्वपूर्ण कारक में परिणत कर दिया। *वियतनाम-भारत*

रणनीतिक साझेदारी पर वियतनाम के प्रधान मंत्री गुयेन टान डंग तथा उनके भारतीय प्रतिस्थानी साझेदार भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा जुलाई 2007 में संयुक्त घोषणापत्र को हस्ताक्षरित किया जाना वियतनाम की लचीली विदेश नीति का एक तार्किक परिणाम था। और तीसरा

वियतनाम रणनीतिक गणनाओं में अमेरिका और जापान व अन्यो के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण कारक है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम के साथ रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देता है , जापान ने अक्टूबर 2006 में वियतनाम के साथ आधिकारिक तौर पर रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की थी। *अमेरिका जुलाई 2011 में रणनीतिक वार्ता संयुक्त वक्तव्य में, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत का अनुबंध और भारत द्वारा पुष्टि की गई अमेरिका-जापान-भारत त्रिपक्षीय रणनीतिक वार्ता का समर्थन करता है जो भारत को अपनी रणनीति को लागू करने के लिए गति प्रदान करता है।*

भारत की भूमिका

शीत-युद्ध समाप्त हो गया लेकिन वियतनाम और भारत के प्राचीन संबंधों का विकसित होना व बने रहना जारी रहा। कम्यूनिस्ट पार्टी वियतनाम (सीपीवी) द्वारा जारी दस्तावेज के अनुसार, शीत युद्ध के बाद के इसके सम्मेलन में, वियतनाम के पारंपरिक मित्र के रूप में हमेशा ही सम्मानित होता रहा है। 1991 में सीपीवी के सातवें सम्मेलन में अपनाया गया संकल्प कहता है कि 'बहुमुखी सहयोग, हमारे देश (वियतनाम) और भारत के साथ-साथ कई स्वतंत्र देशों और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) के बीच मित्रता और एकजुटता विकसित हो रही है'। यह रोचक है कि देशों के नाम शायद ही सीपीवी के सम्मेलन संकल्प में शायद ही उल्लिखित होते हैं।

भारत सहित पारंपरिक साझेदारों की भूमिका सीपीवी के आठवें सम्मेलन में तब जारी रही जब आठवें सम्मेलन में सातवें केंद्रीय समिति की राजनीतिक रिपोर्ट में 'बहुपक्षीय और विदेशी संबंधों में विविधता(वियतनाम)' को महत्व दिया गया और पारंपरिक संबंधों को विकसित करना जारी रहा। 2001 में नौवें सम्मेलन में, सीपीवी ने फिर से 'परम्परागत मित्रों (देशों), स्वतंत्र देशों, एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों , एनएएम में देशों, के साथ एक-दूसरे के विकास के लिए संबंधों का विस्तार करने और एक दूसरे के वैध हितों की रक्षा के लिए समन्वय करने पर जोर दिया।

वास्तव में, वियतनाम की कई पीढ़ियों की सोच में, भारत, कई अन्य लोगों के बीच, वियतनाम का सबसे अच्छा दोस्त है। यही कारण है कि 2007 में *वियतनाम-भारत सामरिक साझेदारी पर संयुक्त घोषणा* से लगभग एक दशक पहले 1999 में उनकी भारत यात्रा पर राष्ट्रपति ट्रान ड्यूक लुओंग ने जोर देकर कहा था कि 'हम दोनों देशों के प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों समान हित और दृष्टिकोण थे और इन्होंने एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित किया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन किया। हम भारत के साथ सहयोग संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक महत्व के रूप में मानते हैं। एक अन्य प्रगति में, फरवरी 2010 में अपनी आधिकारिक भारत यात्रा में, वियतनामी नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने कहा कि 'वियतनाम हमेशा भारत को एक रणनीतिक साझेदार और उभरते विश्व के संदर्भ में एक अपरिहार्य कारक मानता है।

राजनीतिक और रणनीतिक संबंध - पारंपरिक मित्रता से रणनीतिक साझेदारी

भारतीय नेताओं के द्वारा जापान, चीन, थाइलैंड, सिंगापुर, वियतनाम और मलेशिया की यात्राओं के बाद भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय-संवाद साझेदार बन गया। भारत को महसूस हो गया कि आम तौर पर दक्षिणपूर्व एशियाई क्षेत्र और विशेषरूप

से आसियान को भारत की एलईपी का केंद्र बिंदु होना चाहिए।

एलईपी के आलोक में, वियतनाम, शीत-युद्ध को दौरान भारत का एक घनिष्ठ मित्र, नीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण कारक के रूप में सम्मानित किया जाता रहा है। अपने साझेदार मित्र वियतनाम के साथ बात-चीत में प्रधान मंत्री वो वान कीट ने 1994 में हनोई, तत्कालीन प्रधान मंत्री राव नें पुनः जोर दिया कि भारत ने वियतनाम के नवाचार का समर्थन किया है और वियतनाम को विशेष साझेदार का सम्मान दिया है। उसके बाद से, पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह और पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्रमशः 2000 और 2001 में वियतनाम की यात्राएं कीं।

वियतनाम की ओर से 1994 में भारतीय प्रधान मंत्री राव की यात्रा से पहले, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के महासचिव, दो मुओज 1992 में भारत आये थे। उसके बाद वियतनाम के प्रधान मंत्री वो वान कीट जनवरी 1997 में भारत आये थे। भारत-वियतनाम राजनीति संबंधों ने 1990 में भारतीय विशेषज्ञों को यह विश्वास दिलाया कि ये संबंध 'रणनीतिक संबंध' थे।

बल्कि, एशिया-प्रशांत में वियतनाम ही पहला देश था जिसने यह माना कि भारत के साथ इसके संबंध रणनीतिक महत्व के थे। वियतनाम के राष्ट्रपति ट्रान डुक लुओंग की 1999 में भारत की अपनी यात्रा में शब्द 'रणनीतिक' के उपयोग हो जाने के बाद

उन्होंने वियतनाम-भारत संबंधों की सराहना पुनः एक बार तब की जब उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह को मध्य नवंबर 2000 में यह संबोधित किया कि 'वियतनाम भारत को रणनीतिक महत्व देता है'। शब्द 'रणनीतिक' आधिकारिक तौर पर 2003 में भारत गणराज्य और वियतनाम गणराज्य 21वीं सदी में जब व्यापक समन्वय की रूपरेखा पर संयुक्त घोषणा में शामिल हुए थे, तब प्रयोग में लाया गया था। घोषणा में, दोनों पक्ष अपने लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए अपनी साझेदारी के लिए एक रणनीतिक आयाम विकसित करने और एशिया-प्रशांत क्षेत्र और विश्व में शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि में योगदान करने का प्रयास करते हैं। भारत और वियतनाम के मध्य रणनीतिक साझेदारी आधिकारिक रूप से 2007 में तब स्थापित हुई थी जब दोनों देशों के नेताओं ने *भारत-वियतनाम साझेदारी पर संयुक्त घोषणापत्र* पर हस्ताक्षर किये थे। इस घोषणा के साथ वियतनाम दक्षिणपूर्व एशिया में पहला और एशिया प्रशांत में दूसरा (जापान के बाद) देश बन गया जिसने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित की थी।

हाल ही में दोनो देशों के बीच रणनीतिक संवादों के अनेक प्रारूप स्थापित किए गए हैं। वियतनाम-भारत राजनीतिक परामर्शी बैठक सर्वप्रथम 2006 में आयोजित हुई थी और चौथी बैठक अक्टूबर 2009 में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। *रणनीतिक*

साझेदारी पर संयुक्त घोषणा के अनुसार भारत-वियतनाम 'रणनीतिक संवाद को विदेश मंत्रालय में उप मंत्री के स्तर पर स्थापित करने के लिए सहमत हुए'। इसके परिणाम भारत और वियतनाम के मध्य पहला रणनीतिक संवाद 15, अक्टूबर 2009 में आयोजित हुआ। वियतनाम और भारत के बीच दूसरा रणनीतिक संवाद और पांचवा राजनीतिक परामर्शी बैठक अगस्त 2011 में आयोजित हुई। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि दूसरे रणनीतिक संवाद और पाँचवी राजनीतिक परामर्शी बैठक में दोनों देशों के कर्मचारियों ने एससीएस/ईएस विवादों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जो कि एक ऐसा मुद्दा था जो शायद ही द्विपक्षीय वार्ताओं में कभी उल्लिखित किया गया हो।

बातचीत में, दोनों पक्षों ने सभी क्षेत्रों में सहयोग के विषय में भी बात की विशेष रूप से सैन्य एवं सुरक्षा, उच्च-तकनीक, मानव संसाधनों का प्रशिक्षण तथा वियतनाम-भारत रणनीतिक साझेदारी को घनिष्ठ करने की विधियों पर भी बातचीत की। विशेष रूप से वियतनाम एशिया-प्रशांत के अमेरिका, पीआरसी, जापान, मलेशिया और सिंगापुर जैसे उन कुछ देशों में से एक है जिन्होंने हाल के वर्षों में भारत के साथ द्विपक्षीय संयुक्त संवाद आयोजित किये हैं।

शीत युद्ध समाप्त होने के बाद से वियतनाम-भारत रक्षा संबंध सबसे सफल क्षेत्रों में से एक हैं। 1994 में प्रधान मंत्री राव की वियतनाम यात्रा के दौरान, भारत और वियतनाम ने रक्षा सहयोग

पर एक समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए और इस आयोजन के साथ, वियतनाम दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में उन पहले देशों में से एक था जिसने भारत के साथ रक्षा व्यवस्था पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब से भारत गोला-बारूद, प्रणोदक, मिग टायर, पुर्जों और सिल्वर ऑक्साइड विमान बैटरी की आपूर्ति कर रहा है। 2000 में, पूर्व भारतीय रक्षा मंत्री फर्नांडीस की वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम के साथ रणनीतिक मुद्दों पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे: जिनमें संयुक्त नौसेना प्रशिक्षण; एससीएस/ईएस में संयुक्त एंटी-ओसियन पायरेसी अभ्यास; जंगल युद्ध प्रशिक्षण; आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण; भारत में वायु सेना के पायलटों का प्रशिक्षण; वियतनाम वायु सेना के लड़ाकू विमानों (एमआईजी) के लिए भारत का मरम्मत कार्यक्रम शामिल थे। 2007 में वियतनाम की अपनी यात्रा में, भारतीय रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने अपने समकक्ष जनरल फुंग क्वांग थान के साथ एक बैठक में घोषणा की कि भारत पेटा वर्ग के जहाजों से संबंधित नौसैनिक पुर्जों के 5,000 आइटमों को वियतनाम को स्थानांतरित करेगा। उन्होंने 2008 की पहली छमाही में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों पर प्रशिक्षण देने के लिए चार सदस्यीय दल को तैनात करने की भी घोषणा की। दोनों पक्ष रक्षा सहयोग पर समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भी सहमत हो गए। वियतनामी रक्षा मंत्री जनरल फुंग क्वांग थान ने 4-8 नवंबर, 2009 तक भारत की यात्रा की और दोनों रक्षा मंत्रियों द्वारा यात्रा के दौरान

एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए गए।

शीत युद्ध के बाद , भारत ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपने नौसैनिक जहाज की यात्रा को फिर से शुरू किया और 1998 के बाद से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भी यह यात्राएँ शुरू हुईं और वियतनाम तब से एशिया-प्रशांत के लिए भारतीय नौसेना के अधिकांश जहाजों की यात्रा के लिए एक गंतव्य बन गया है। तीन भारतीय नौसैनिक जहाज- आईएनएस राजपूत, आईएनएस दिल्ली और आईएनएस खंजर ने 1 से 4 अक्टूबर, 1998 के दौरान वियतनाम की सद्भावना यात्रा की। भारतीय नौसेना जहाज (आईएनएस) राजपूत, आईएनएस मुंबई और आईएनएस ज्योति, और इंडिया कोस्ट गार्ड शिप (सीजीएस) संग्राम ने क्रमशः 2000, 2001 और 2003 हो ची मिन्ह सिटी की सद्भावना यात्रा की। तब से, भारतीय नौसेना ने दा नांग के मध्य प्रांत में टीएन सा बंदरगाह पर सद्भावना यात्राओं पर तीन नौसैनिक जहाजों, आईएनएस राजपूत, आईएनएस कुलिश और आईएनएस किरपान को तैनात किया। मई 2007 में, दो भारतीय नौसैनिक जहाजों, आईएनएस मैसूर और आईएनएस रंजीत, और भारतीय तटरक्षक जहाज सागर ने हो ची मिन्ह सिटी की सद्भावना यात्राएं की। आईएनएस कोरा और आईएनएस किरपान, भारत के दो नौसैनिक जहाजों ने 17 से 21 अप्रैल, 2008 तक हैह फोंग का दौरा किया। हाई ह्यॉन्ग भी, 2009 और 2010 के वर्षों में भारतीय नौसैनिक जहाजों की यात्राओं का गंतव्य था। भारतीय नौसेना पोत,

आईएनएस ऐरावत ने 19 से 28 जुलाई, 2011 के दौरान वियतनाम में न्हा ट्रांग और है फोंग की सद्भावना यात्राएं की थी।

हनोई प्रांत के निकट हयोंग प्रांत में भारत के नौसैनिक जहाजों की वियतनाम यात्रा की आवृत्ति ने उस विश्वास को आकार दिया जिसके कारण भारत सरकार के स्रोत डेक्कन क्रॉनिकल द्वारा हवाला दिया गया कि 'यह कदम भारत को दक्षिण चीन सागर में एक स्थायी उपस्थिति की कुंजी देगा'। हालांकि वियतनाम और कुछ आसियान सदस्य पक्षकारों के तौर पर एससीएस/ईएस के पूर्ण व कुछ हिस्से पर संप्रभुता का दावा करते हैं, उस स्थिति में इस क्षेत्र में भारत की नौसेना की उपस्थिति को क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए एक स्थिरक के रूप में देखा जा रहा है।

अपनी नौसेना की उपस्थिति के साथ, *अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर एससीएस/ईएस विवादों* को सुलझाने एवं अंतर्राष्ट्रीय पानी में नौवहन की स्वतंत्रता एससीएस/ईएस मुद्दे पर भारत के विचार बिंदु में एक सफलता थी। यदि 2010 में, हनोई में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने एससीएस/ईएस में भारत के शामिल होने की नीव रखी तो 2011 में हुई नयी प्रगति इसे निश्चित रूप से तब लुक ईस्ट पालिसी के नये चरण में ले गयी जब इसने आधिकारिक तौर पर एससीएस/ईएस में नौवहन की स्वतंत्रता को सराहा था और संबंधित पक्षों को 1982 के यूनाईटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ दि लॉ

ऑफ दि सी (यूएनसीएलओएस) तथा 2002 के *साउथ चाइना सी (डीओसी)* में पक्षकारों के आचरण की घोषणा का समर्थन करने की विनती की थी।

न्यूज रिपोर्टरों द्वारा भारतीय नौसेना जहाज व चीन के पोत के मध्य जुलाई 2011 में वियतनाम के समुद्रीतट पर हुए कथित विरोध के विषय में पूछे जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि 'भारत दक्षिण चीन सागर सहित अंतर्राष्ट्रीय पानी में स्वतंत्र नौपरिवहन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्वीकार्य सिद्धान्तों के क्रम में गलियारे के अधिकारों का समर्थन करता है'। इन सिद्धान्तों का सभी के द्वारा आदर किया जाना चाहिए। भारत फिर एससीएस/ईएस में अपनी भागीदारी में आगे बढ़ा जब प्रवक्ता विष्णु प्रकाश ने 16, सितंबर 2011 को नई दिल्ली में इस बात पर जोर दिया कि 'दक्षिण चीन सागर में नौपरिवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करो और उम्मीद करो कि इस विवाद के सभी पक्षगण दक्षिण चीन सागर में आचरण पर 2002 के घोषणापत्र का अनुपालन करेंगे'। इससे पहले एक अन्य प्रगति में, दूसरे वियतनाम-भारत रणनीतिक संवाद में भाग लेने वाले कर्मचारियों ने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के साधारण मामलों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। वियानम में भाग लेने वाले इंडिया-स्ट्रेटेजिक डायलॉग ने आम चिंताओं के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और अंतर्राष्ट्रीय

कानूनों, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस 1982) एवं पूर्व समुद्र (डीओसी) में पार्टियों के आचरण पर घोषणा के संबंधित पक्षों का गंभीर अवलोकन के आधार पर शांतिपूर्ण समाधान के माध्यम से पूर्वी समुद्र (दक्षिण चीन सागर) का समाधान करने पर सहमत हुए।

इसके अलावा, भारत ने कभी भी कठिनाइयों (शायद संवेदनशील), को विशेष रूप से एससीएस/ईएस विवाद से जुड़ी हुई, को चीन के साथ अपने संबंधों में नहीं छुपाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सितंबर 2011 में घोषणा की थी कि दक्षिण चीन सागर में वियतनामी समुद्री तट से 45 मील की दूरी पर Nha Trang के वियतनामी बंदरगाह से Hai Phong की ओर नौकायन करते समय भारतीय नौसेना पोत, आईएनएस ऐरावत से एक कॉलर द्वारा खुले रेडियो चैनल पर खुद को 'चीनी नौसेना' के रूप में बताते हुए इस वक्तव्य के साथ कि 'आप चीनी पानी में प्रवेश कर रहे हैं', संपर्क किया गया था। दूसरी प्रगति में भारत ने एससीएस/ईएस में वियतनाम के संपूर्ण प्रभुत्व वाले आर्थिक जोन में चीन की संप्रभुता के दावे को देखा, विशेषरूप से जब चीन ने वियतनाम के ईईजैड में भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) की तेल खोज पर चीन की आपत्ति का कोई कानूनी आधार नहीं था। सितंबर 2011 में हनोई की तीन दिवसीय यात्रा पर, भारत के विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने अपने वियतनामी

समकक्ष फाम बिंह मिन्ह से कहा कि हम विवादित क्षेत्र में या दो अपतटीय ब्लॉक जिन पर वियतनाम का दावा है, में भारत के ओएनजीसी विदेश में तेल और गैस की खोज में आगे बढ़ेंगे। रक्षा राज्य मंत्री एम.एम. पल्लम राजू ने 16 सितंबर, 2011 को एससीएस/ईएस में अपने अधिकारों की रक्षा में भारत की तत्परता पर जोर देते हुए कहा कि 'मुझे लगता है कि कोई भी राष्ट्र जो अपने अधिकार का दावा करना चाहता है , ... एक देश के रूप में , हम अपने अधिकारों और रुचियों के विषय में बहुत स्पष्ट हैं। हम अपने हितों की बहुत मजबूती से रक्षा करेंगे।

वियतनाम-भारत के बीच के संबंधों के विषय में उपरोक्त वर्णित नयी प्रगतियां 'वास्तव में भारत-वियतनाम संबंधों को नये स्तर पर ले गई हैं'।

आर्थिक सहयोग - को अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है

हालांकि वियतनाम-भारत राजनीतिक एवं रणनीतिक संबंधों में उठाए गए मजबूत कदम भी उनके द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की धीमी प्रगति की वास्तविकता को छुपा नहीं पाए। वियतनाम-भारत व्यापार संबंधों के धीमे विकास को उनके द्विपक्षीय व्यापार तथा व्यापार समन्वय के रूप में देखा जा सकता है।

वियतनाम-भारत द्विपक्षीय व्यापार मूल्य आश्चर्यजनक रूप से

1990 के मध्य से बढ़ा है, जो वि.व. 1996-1997 में 119.77 मिलियन अमेरिकी डालर से वि.व. 2006-2007 में 1,153.07 मिलियन अमेरिकी डालर पहुँचा, जिसमें 862.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई, अथवा जो कि वार्षिक आधार पर 86.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जोकि विश्व के साथ भारत के व्यापार की तुलना में वृद्धि दर से काफी अधिक है, जो कि वैश्विक स्तर पर 33.0 प्रतिशत वार्षिक (वि.व. 1996-1997 में भारत का कुल व्यापार मूल्य 72,603.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जो वि.व. 2006-2007 में 312,149.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहुँच गया) तक बढ़ा था। वियतनाम के सामान्य सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वियतनाम-भारत द्विपक्षीय व्यापार 1995 में 97.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 2006 में 1,018.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया है जो कि दस वर्षों में 944.20 प्रतिशत तक अथवा 94.4 प्रतिशत वार्षिक स्तर पर बढ़ा, जो कि वियतनाम के मुकाबले काफी अधिक लगभग 36.0 प्रतिशत वार्षिक (वियतनाम का कुल व्यापार मूल्य 1995 तथा 2006 में क्रमशः 18,399.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 84,717.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहुँच गया) बढ़ा। हालाँकि द्विपक्षीय व्यापार मूल्य 2008 में 2,483.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहुँचा, भारत के साथ वियतनाम का व्यापार 1990 से घाटे में आ गया जो अविश्वसनीय रूप से 1995 में 51.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के घाटे से 2008 में

1,107.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में एक सुखद संकेत यह है कि वियतनाम के कुल निर्यात मूल्य में भारत का हिस्सा 2007 में 0.37 प्रतिशत से बढ़कर 2010 में 1.37 प्रतिशत हो गया। वियतनाम के कुल व्यापार में भारत का हिस्सा भी 2007 में 1.26 प्रतिशत से 2010 में 1.72 प्रतिशत तक संवर्धित हुआ है। इसके अलावा, वियतनाम-भारत व्यापार विनिमय में वियतनाम का व्यापार घाटा 2007 में 1,177.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2010 में 770.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

इस तथ्य के बावजूद कि वियतनाम के व्यापार में भारत का अनुपात बढ़ा है, पूर्व के कुल व्यापार में उत्तरार्द्ध की हिस्सेदारी वास्तव में कम थी। व विपरीततया। 1996 में वियतनाम के कुल आयात और निर्यात में भारत का केवल 0.19 प्रतिशत और 0.75 प्रतिशत का योगदान था और 2008 के उत्तरार्ध में वियतनाम के व्यापार में भारत के अनुपात में लगातार सुधार हुआ है, लेकिन पूर्व में कुल निर्यात का केवल 0.62 प्रतिशत और कुल आयात का 2.59 प्रतिशत था। भारत के कुल व्यापार में वियतनाम के अनुपात की वर्तमान स्थिति को देखते हुए निराशा भी हुई। वि.व. 1996-1997 में, वियतनाम में कुल निर्यात का केवल 0.05 प्रतिशत और भारत के कुल आयात का 0.004 प्रतिशत था। भारत के व्यापार में वियतनाम की हिस्सेदारी में सुधार हुआ है, लेकिन पूर्व में कुल

निर्यात का केवल 0.06 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2010-2011 के उत्तरार्द्ध के कुल आयात का 0.29 प्रतिशत था (तालिका 3 देखें)।

तालिका 2: भारत के साथ वियतनाम का व्यापार

(अमेरिकी डॉलर में)

	1995	2000	2004	2008	2009	2010 (prel.))
भारत को कुल निर्यात	10.4	47.2	78.6	389.0	419.6	991.6
भारत से कुल आयात	61.5	178.4	593.5	2,094. 3	1,536. 1	1,762. 0
व्यापार का संतुलन	-51.1	-131.2	-514.9	- 1,705. 3	- 1,116. 5	-770.4
<i>निर्यात</i>						
भारत को	10.4	47.2	78.6	389.0	419.6	991.6
विश्व को	5,448. 9	14,482 .7	26,485 .0	62,685 .1	57,096 .3	72,191 .9

वियतनाम के वैश्विक निर्यातों में भारत का प्रतिशत में हिस्सा	0.19	0.32	0.30	0.62	0.73	1.37
आयात						
भारत से	61.5	178.4	593.5	2,094.3	1,536.1	1,762.0
विश्व से	8,155.4	15,636.5	31,968.1	80,713.8	69,948.8	84,801.2
वियतनाम के वैश्विक आयातों में भारत का प्रतिशत में हिस्सा	0.75	1.14	1.86	2.59	2.19	2.08

स्रोत: 2002, 2005 और 2010 के दौरान वियतनाम का सामान्य सांख्यिकी कार्यालय।

तालिका 3: वियतनाम के साथ भारत का व्यापार

(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

	1996-97	2000-01	2004-05	2008-09	2009-10	2010-11
निर्यात						
वियतनाम को	118.07	225.90	555.96	1,738.65	1,838.95	2,659.56
विश्व को	33,469.95	44,560.29	83,535.94	185,295.36	178,751.43	251,135.89
भारत के वैश्विक निर्यात में वियतनाम का प्रतिशत	0.3528	0.5070	0.6655	0.9383	1.0288	1.0590
आयातs						
वियतनाम से	1.70	12.39	86.50	408.66	521.81	1,064.90
विश्व से	39,132.41	50,536.45	111,517.43	303,696.31	288,372.88	369,769.13

भारत के वैश्विक आयात में वियतनाम का प्रतिशत	0.0043	0.0245	0.0776	0.1345	0.1809	0.2880
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

स्रोत: वाणिज्य विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत), से प्राप्त डेटा की गणना, *निर्यात आयात डेटा बैंक वर्जन 6.0 - ट्रेडस्टैट*, <http://commerce.nic.in/eidb/default.asp>.

निवेश: दो देशों के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को समझना कठिन है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत) के अनुसार अगस्त 1991 से दिसंबर 2005 के दौरान, वियतनाम ने भारत में मात्र 0.1 मिलियन अमेरिकी डालरों का निवेश किया था। इसी स्रोत के अनुसार अगस्त 1991 से अप्रैल 2011 के दौरान भारत में वियतनाम का कुल निवेश 0.13 अमेरिकी डालर था जबकि वियतनाम की विदेशी निवेश एजेन्सी, वियतनाम योजना एवं निवेश मंत्रालय के अनुसार 28 फरवरी 2010 तक वियतनाम का बाह्य निवेश 17.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। वियतनाम की विदेशी निवेश एजेन्सी, वियतनाम योजना एवं निवेश मंत्रालय

द्वारा प्रदत्त डेटा दर्शाता है कि वियतनाम की कुल 575 वैध परियोजनाओं में से भारत में 650,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं का निवेश भारत में किया गया था।

हाल के वर्षों में वियतनाम में भारत का निवेश भी खराब रहा है। वियतनाम-भारत *रणनीतिक समझौते के जुलाई, 2007 में हस्ताक्षरित होने से पहले, टाटा स्टील ने* हा तिन्ह के केंद्रीय प्रांत में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलरों का निवेश करने का निर्णय लिया था। बा रिया-वुंग ताउ के एक प्रांत में स्टील संयंत्र की स्थापना के लिए 527.3 मिलियन अमेरिकी डॉलरों का निवेश करने का प्रमाणपत्र भारत के एक दूसरे इस्पात निर्माण समूह एस्सार को दिया गया। उस समय भारत वियतनाम में निवेश करने वाले शीर्ष 10 निवेशकों में शामिल था। हालांकि, उद्देश्यीय और विषयात्मक दोनों प्रकार की कठिनाइयों ने एस्सार और टाटा दोनों के प्रयासों को इसके निवेश के पैमाने को सीमित करने पर मजबूर कर दिया। प्रमाणपत्र प्राप्त करने के मात्र 13 महीनों में ही एस्सार ने परियोजना से पीछे हटने का निर्णय ले लिया। अगस्त 2010 तक टाटा भी अपनी प्रारंभिक योजना को कार्यान्वित नहीं कर पाया, हालांकि वीएन स्टील तथा वीसेम (वियतनाम सीमेंट इंडस्ट्री कार्पोरेशन) के साथ यह समन्वय समझौते को 2007 में हस्ताक्षरित कर चुका था। एक छोटे पैमाने के निवेश के लिए अनुमोदन के लिए अपने दस्तावेजों को पुनः जमा करना पड़ा। इसी

के परिणामस्वरूप भारत वियतनाम में सबसे छोटा निवेशक बन गया।

वियतनाम के विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रदान किये गए डेटा के अनुसार, वियतनाम में कुल 88 देशों और राज्यक्षेत्रों निवेशकों में से सितंबर 2009 तक भारत 201.1 मिलियन अमेरिकी डॉलरों के निवेश के साथ 32वें स्थान पर था। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय निवेश पर वेल कोलंबिया सेंटर के द्वारा 22 सितंबर 2010 जारी एक अध्ययन दर्शाता है कि वियतनाम 1996-2002 के दौरान भारत के बाहरी निवेशों में 8वें स्थान पर था। हालांकि, 2002-2009 के दौरान वियतनाम भारत के बाह्य निवेशकों में से शीर्ष 15 में से गायब था।

मानव विकास समन्वय- एक सफल क्षेत्र

यदि व्यापार और एफडीआई के क्षेत्र में वियतनाम और भारत के बीच संबंधों को सुधारे जाने की आवश्यकता है तो, वियतनाम के मानव संसाधन में भारत के योगदानों, द्विपक्षीय संबंधों की रूपरेखा और *आसियान* एकीकरण (*आईएआई*) की पहल के प्रति भारत के समर्पण दोनों को अत्यधिक सराहा और आगे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। *वियतनाम* को कई छात्रवृत्ति योजनाओं जैसे कि दि इंडियन टैक्निकल एंड इकानामिक कोऑपरेशन (*आईटीईसी*) कार्यक्रम, सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना (जीसीएसएस) तथा *मेक्यॉग गंगा* को-ऑपरेशन *छात्रवृत्ति योजना* (एमजीसीएसएस) के

अंतर्गत कई स्थान प्रदान किये गए थे। भारत हर वर्ष आईटीईसी कार्यक्रम के अधीन वियतनाम को 95 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। आईटीईसी योजना के अलावा, वियतनाम को जीसीएसएस के अधीन 10 स्थान और आईसीसीआर सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (सीईपी) के अधीन 20 स्थान आबंटित किये जाते हैं। 2006, के बाद से वियतनामी छात्रों को एमजीसीएसएस के अधीन प्रत्येक वर्ष 10 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

कंबोडिया के नोम पेन्ह में 8वें आसियान शिखर सम्मेलन में आसियान एकीकरण कार्य योजना (आईएआई) 2002- 2008 के लिए पहल को राष्ट्र/सरकार के प्रमुखों द्वारा 4 नवंबर 2002 को अपनाया गया, जिसका लक्ष्य आसियान के सदस्य देशों के बीच विकास के अंतर को कम करने के उद्देश्य से नए 'सदस्य देशों की सहायता करना', और अधिक से अधिक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना, समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम (सीएलएमवी) में गरीबी को कम करने में मदद करना था। कार्य योजना मुख्यरूप से, बुनियादी ढांचे के विकास, मानव संसाधन विकास, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और सीएलएमवी देशों में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

आसियान के संवाद भागीदार के रूप में, भारत ने अपनी ठोस

प्रतिबद्धताओं के माध्यम से आईएआई कार्य योजना का समर्थन किया। 2002 में पहले आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि, 'भारत ने आसियान एकीकरण (आईएआई) के लिए पहल और आईएआई परियोजनाओं में भाग लेने के लिए अपनी प्रतिबद्धता, विशेष रूप से एचआरडी में, और नए आसियान सदस्यों की सहायता के लिए समर्थन व्यक्त किया है'। 2005 में 4वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किये गए छह प्रस्तावों में से एक के अंतर्गत छात्रों व सिविल सेवकों, पेशेवरों और व्यवसायियों को पर्याप्त अंग्रेजी भाषा और संचार कौशल के साथ अंग्रेजी भाषा कौशल में दक्ष करने के लिए कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम में अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण (सीईएलटी) के लिए स्थापित किये जाने वाले स्थायी केंद्र को स्थापित किया जा रहा है। एक नयी प्रगति में, आसियान आईएआई 2 (2009-2015) में लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) विकास क समर्थन करने की योजना, 'भारत द्वारा स्थापित उद्यमिता विकास केंद्रों को ध्यान में रखते हुए सीएलएमवी देशों में उद्यमिता के निर्माण के लिए परियोजनाओं की एक श्रृंखला आयोजित करने पर जोर देती है'।

सीएलएमवी के सदस्य के रूप में, वियतनाम को आईएआई कार्य योजना और आईएआई कार्य योजना 2 के लिए भारत की

प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा में भारत द्वारा समर्थित किया गया है।
 दा नांग में *वियतनाम-भारत अंग्रेजी प्रशिक्षण केंद्र*
(वीआईसीईएलटी) फरवरी 2010 में खोला गया था। इससे पहले,
वियतनाम-भारत उद्यमिता विकास केंद्र (वीआईईडीसी) की स्थापना
 अक्टूबर 2005 में हनोई में की गई थी और 2008 तक कम से
 कम तीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए जा चुके थे। नवीनतम
 घटना में, वियतनाम-भारत उन्नत संसाधन केंद्र सूचना और संचार
 प्रौद्योगिकी (एआरसी-आईसीटी) को 16 सितंबर, 2011 को
 भारतीय विदेश मंत्री एसएम कृष्णा की वियतनाम यात्रा के अवसर
 पर हनोई में लॉन्च किया गया था। यह केंद्र भारत के सेंटर फॉर
 डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) की सहायता से
 संचालित होगा।

संभावनाएं और संस्तुतियां

रणनीतिक और राजनीतिक आयाम:

कई दशकों में पारंपरिक वियतनाम-भारत संबंध दोनों देशों और
 इसके लोगों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। यह दोनों देशों के बीच
 वर्तमान संबंधों का ठोस आधार है। 2007 में रणनीतिक साझेदारी
 की स्थापना ने दोनों भागीदारों के बीच आपसी विश्वास और
 पारस्परिक हितों को प्रकट किया। वियतनाम-भारत रणनीतिक
 संवाद और राजनीतिक परामर्श बैठक रणनीतिक और राजनीतिक

आयामों में द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए प्रभावी सहयोग तंत्र बन गए हैं। संबंध की निरंतर प्रगति के साथ, मौजूदा वियतनाम-भारत रणनीतिक साझेदारी के शीघ्र ही व्यापक रणनीतिक साझेदारी बनने की संभावना है।

महत्वपूर्ण ढंग से भारत का 97 प्रतिशत से अधिक आयतन में व्यापार तथा 75 प्रतिशत से अधिक मूल्य में व्यापार समुद्र आधारित है। यदि कोई 'व्यापार की दिशा', का अध्ययन करता है तो 50 प्रतिशत के लगभग भारतीय व्यापार पूर्व आधारित है और मलक्का जलमार्ग से लगभग प्रतिवर्ष 60,000 जहाजों के द्वारा पारगमन होता है। उस संदर्भ में, मलक्का और एससीएस/ईएस के जलमार्ग के माध्यम से व्यापारी की सुरक्षा और बचाव भारत के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब आसियान-भारत आर्थिक गलियारा चेन्नई (भारत) को हो ची मिन्ह सिटी (वियतनाम) से जोड़ता है। मलक्का जलमार्ग या आसियान-भारत आर्थिक गलियारे के माध्यम से भारत और आसियान राज्य के सदस्यों के व्यापार को तब तक धमकी दी जाएगी जब तक ईएस/एससीएस में नौवहन की स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षित नहीं हो जाती।

हालांकि, अगर कोई संप्रभु दावेदार यूएनसीएलओएस 1982 की परवाह किए बिना पूरे समुद्र पर प्रभावी ढंग से कब्जा कर लेता है तो ईएस और एससीएस में डीओसी और कानूनी रूप से बाध्यकारी आचार संहिता (सीओसी) के माध्यम से एससीएस/ईएस में नौवहन की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। अन्य देशों की तरह

जिन्हें एससीएस/ईएस में नौवहन की स्वतंत्रता में रूचि है, एससीएस/ईएस में विवाद को सुलझाने के सामूहिक तंत्र का समर्थन करने (जैसा कि रक्षा मंत्री एंटोनी ने हनोई, 2010 में एडीएमएम+ में कहा था) और “खुला” एससीएस/ईएस अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को आदर करने के लिए कहना (जैसा कि विदेश मंत्री एस. एस. कृष्णा ने 2012 में दिल्ली संवाद IV में स्पष्ट किया है) यह भारत के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों (विशेषकर ईईजेड के नियमों) के लिए सम्मान एससीएस/ईएस में अपनी तेल और गैस की खोज परियोजनाओं को जारी रखने के लिए भारत का आधार है। दूसरे शब्दों में, वियतनाम-भारत संबंध सबसे अच्छी तरह से प्रस्तुत होंगे यदि ये मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय नियमों और कानूनों के अनुरूप होंगे।

हाल ही में, वियतनाम और रूस कथित तौर पर दि रसिया अर्बन (एसएस-एन-25 स्विचब्लेड) वर्जन, एंटी-शिप मिसाइलों का उत्पादन 2012 में प्रारंभ कर रहे थे। एशिया-प्रशांत में बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के संदर्भ में सैन्य आधुनिकीकरण न केवल वियतनाम के लिए बल्कि क्षेत्र के अन्य छोटे देशों के लिए भी एक बाध्यकारी कर्तव्य है। इसका तात्पर्य है कि, वियतनाम हथियारों के आयात और हथियार उत्पादक सहयोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार होगा जो कि किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। हथियारों और सैन्य उपकरणों के एक प्रमुख उत्पादक में से एक होने के तौर पर भारत को वियतनाम-रूस ढांचे को अपनाना

चाहिए।

आर्थिक सहयोग

2007 में जब वियतनाम को भारत के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार समझा गया, तो भारत कई कृषि उत्पादों में वियतनाम के लाभ के विषय में सतर्क हो गया। भारत की राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण से, अगस्त 2009 में आसियान- भारत एफटीए ऑन ट्रेड इन गुड्स पर हस्ताक्षर किए गए और यह 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ।

वियतनाम-भारत व्यापार विनिमय 2009 में 1.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 2010 में 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और उल्लेखनीय रूप से , भारत के साथ व्यापार करने में वियतनाम का घाटा 1.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 770 मिलियन अमेरिकी डॉलर (तालिका 2 देखें) हो गया। वस्तु व्यापार में आसियान-भारत एफटीए के संदर्भ में , वियतनाम-भारत व्यापार विनिमय आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ेगा। सेवाओं और निवेश में एफटीए व्यापार पर आसियान-भारत वार्ता की प्रगति संभवतया सामान्य रूप से आसियान-भारत आर्थिक संबंधों और विशेष रूप से वियतनाम-भारत आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक मजबूत रूपरेखा बन जाएगी।

एससीएस/ईएस में वियतनाम के ईईजेड में तेल और गैस की

खोज में सहयोग दोनों देशों के बीच संयुक्त निवेश का एक महत्वपूर्ण मामला बनने की क्षमता धारित करता है। इस ओर से वियतनामी निवेशक हाल के वर्षों में अधिक मजबूत बन रहे हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि वियतनाम से प्रत्येक बाहरी निवेश की औसत लागत 28 फरवरी 2010 तक 17.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी लेकिन पिछले दो दशकों में भारत में वियतनाम की एक छोटी सी परियोजना ही रही है। वियतनामी निवेशकों के पास छोटे-पैमाने की जल-विद्युत परियोजनाओं में निवेश करने सुविधा रही है जबकि कथित तौर पर भारत को जल-विद्युत परियोजनाओं के साथ ऊर्जा के अन्य संसाधनों की भी आवश्यकता है। इसलिए, भारत में वियतनामी निवेशकों के लिए छोटे पैमाने पर जल विद्युत, एक संभावित क्षेत्र हो सकता है। इसके अलावा, वियतनामी निवेशक हाल ही में कंबोडिया और लाओस में निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कारक बन गए हैं। जबकि भारत को इन दोनों देशों में अधिक उपस्थिति की आवश्यकता है इसलिए वियतनाम और भारत के निवेशकों के बीच सहयोग को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

भारत-वियतनाम आर्थिक संबंधों को दक्षिण-पूर्व एशियाई मुख्य क्षेत्र के दायरे में बढ़ाया जा सकता है जहां क्षेत्रों में कई आर्थिक मार्ग प्रस्तुत किए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में मावलमीन (म्यांमार को जोड़ने वाला) और बैंकॉक के बुनियादी ढांचे के बाद से डोंगा

और दनांग (वियतनाम के) को जोड़ने वाले आसियान-भारत आर्थिक गलियारे और ईस्ट-वेस्ट आर्थिक गलियारे के बीच संपर्कता का उल्लेख किया जाना चाहिए चूंकि बैंकाक की ढांचागत व्यवस्था(आसियान-भारत आर्थिक कारिडोर के मुख्य स्थानों में से एक) से मुकदहां बॉर्डर गेट (ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण बिंदु) परिवहन और अन्य सेवाओं की मांगों को पूरा कर सकता है।

मानव विकास

भारत द्वारा दशकों से वियतनाम को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के कई रूपों की निरंतरता, आईटीईसी की रूपरेखा में अधिक छात्रवृत्ति स्थान बढ़ाने के भारत के हाल के फैसले और वियतनाम-भारत अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण केंद्र और वियतनाम-भारत उद्यमिता विकास केंद्र ने वियतनाम के क्षमता निर्माण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हाल के वर्षों में वियतनाम अपनी नियोजित परमाणु संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए मानवबल को प्रशिक्षित करता आ रहा है। 'अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को उन्नत करने हेतु परमाणु तकनीक का विकास करने में, वियतनाम की मांग को पूरा करने में वियतनाम में परमाणु संयंत्रों का निर्माण व उनकी निगरानी' के उद्देश्य से हनोई विज्ञान विश्वविद्यालय का *इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर इंजीनीयरिंग* और *इन्वाँयरोन्मेंट*

फिजिक्स की स्थापना 2008 में की गई थी। उस संदर्भ में , भारत इस क्षेत्र में मानव संसाधनों के प्रशिक्षण के लिए प्रवक्ताओं और पाठ्यक्रम दोनों को प्रदान करने में सहायता कर सकता है। इसके अलावा, अंतरिक्ष विज्ञान, प्रारंभ में उपग्रहों का प्रक्षेपण और निगरानी, वियतनाम और भारत के बीच एक संभावित सहयोग है। इस क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक के रूप में , भारत उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में भाग ले सकता है और वियतनाम की उपग्रह प्रणालियों की निगरानी के लिए उसके कार्यबल को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है।

दोनों देशों के बीच विद्वानों के आदान-प्रदान को गति दी जानी चाहिए। यह दोनों ओर के शैक्षणिक क्षेत्र के लिए ज्ञान को उन्नत करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी तरीका है। दोनों देशों के बीच गहराई से समझने और सही मायने में एक-दूसरे पर भरोसा करने का यह सबसे छोटा तरीका हो सकता है।

निष्कर्ष

अपने उद्भव से कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने के बाद से यह कहना उचित है कि 'लुक ईस्ट' शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत की सफलतम नीतियों में से एक है। एलईपी का धन्यवाद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में हितधारकों में से एक है, ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा के केंद्रों तथा विश्व में आर्थिक लाभों के लिए एक है।

एक पारंपरिक साझेदार के तौर पर वियतनाम को एलईपी में एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर मान्यता दी गई है। भारत की एलईपी और वियतनाम की नीति जो अपने मित्रों से संबंधों को प्रगाढ़ करने और बहुस्तरीय बनाने और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विविधता प्रदान करने का रहा है उसने वियतनाम-भारत रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की है। वियतनाम-भारत के संबंधों ने पिछले दो दशकों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें दोनो देश द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर सहयोग कर सकते हैं। वियतनाम-भारत रणनीतिक साझेदारी का हस्ताक्षरित होने के दो लोगों के मध्य दोस्ती और खुशहाली के लिंचपिन बनने की संभावना है तथा ये एशिया-प्रशांत क्षेत्र और बड़े स्तर पर विश्व के लिए शांति, सहयोग और विकास की स्थापना का संकेत है।

HHH

ENDNOTES

1. Acharya, Alka (2007 June), India's Look East Policy: Regional Strategy or A Rising Power, paper presented at the Commemorative Seminar to mark

the 35th Anniversary of the Establishment of Full Diplomatic Relations between India and Vietnam, Hanoi.

2. Rao, Narasimha P.V. (1994), *India and the Asia-Pacific: Forging a New Relationship*, ISEAS, Singapore, p.2.

3. Ram, Amar Nath(2012), Introduction, in Ram, Amar Nath (Ed.), *Two Decades of India's Look East Policy: Partnership for Peace, Progress and Prosperity*, Manohar, p.15.
4. Ministry of External Affairs (Government of India), *Annual Report 1995-1996*, pp.7&118.
5. Ministry of External Affairs (Government of India), *Annual Report 1995-1996*, pp.7&118.
6. Ministry of External Affairs (Government of India), *Annual Report 2006-2007*, p. 122.
7. Kesavan, K.V. (Ed.) (2000), *Building a Global Partnership: Fifty Years of Indo-Japanese Relations*, Lancer Books, p. 78&135.
8. Mansingh, Lalit (2012), The Look East Policy and Its Implications for Eastern India, in Ram, Amar Nath Ram (Ed)., *Two Decades of India's Look East Policy: Partnership for Peace, Progress and Prosperity*, Manohar, p.197.
9. Mukherjee, Pranab (2007), *India's Look East Policy: Implications for Thailand and Southeast Asia*, Keynote Address at the Institute for Security and International Studies (ISIS), Chulalongkorn

University._

<http://meaindia.nic.in/mystart.php?id=530113127>

10. Ram, Amar Nath, op.cit., p.15.
11. Sinha, Yashwant (2003, August) at the Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore, '*Asia: A Period of Change*'. http://indianembassy.ru/cms/index.php?Itemid=626&id=241&option=com_content&task=view
12. Kapur, Pradeep Kumar (2007, June), *India's Engagement with East Asia*, paper presented at the Commemorative Seminar to mark the 35th Anniversary of the Establishment of Full Diplomatic Relations between India and Vietnam, Hanoi.
13. Devare, Sudhir (2006), *India & Southeast Asia: Towards Security Convergence*, ISEAS, Singapore, p.15.
14. Mohan, Raja C. (2003, October), Look East Policy: Phase Two, *The Hindu*. <http://www.hindu.com/2003/10/09/stories/2003100901571000.htm>

15. India calls for cooperative approach to ensure security of sea lanes, *AsianMilitary Review*, October 12, 2010. <http://www.asianmilitaryreview.com/News/index.php?hNewsId=1359>
16. Ladwig III, Walter C. (2010), India and the Balance of Power in the Asia-Pacific, *JFQ*, Issue 57, 2nd quarter, p.115.
17. *The Economic Times* (2012 January), India, Thailand resolve to conclude FTA by June-July. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-01-25/news/30663065_1_asean-bilateral-trade-indian-investments
18. *Deccan Herald* (2010 October), Manmohan for early India-ASEAN FTA in services, investment, <http://www.deccanherald.com/content/108941/manmohan-early-india-asean-fta.html>
19. Mukherjee, Pranab Keynote Address (2007, February) at the 9th Asian Security Conference on 'Security Dynamics in Southeast Asia: Emerging Threats & Responses' organised by IDSA, New Delhi. <http://www.indembkwt.org/press/feb0907.1.htm>

20. Nanda, Prakash (2003), *Rediscovering Asia - Evolution of India's Look East Policy*, Lancer Publishers & Distributors, p.469.
21. Sikri, Rajiv (2007 September), India's Foreign Policy Priorities in the Coming Decade, *ISAS Working Paper*, No. 25, p.47.
22. *Hanoi joint declaration on the first ADMM+ issued*, 13/10/2010, [http://english.vietnamnet.vn/politics/201010/Hanoi-joint-declaration-on-the-first-adMM-issued-941934/http://english.vietnamnet.vn/politics/201010/Hanoi-joint-declaration-on-the-first-adMM-issued-941934/](http://english.vietnamnet.vn/politics/201010/Hanoi-joint-declaration-on-the-first-adMM-issued-941934/http://english.vietnamnet.vn/politics/201010/Hanoi-joint-declaration-on-the-first-adMM-issued-941934/http://english.vietnamnet.vn/politics/201010/Hanoi-joint-declaration-on-the-first-adMM-issued-941934/)
23. Rao, Nirupama (2011, July), *address at the "Maritime Dimensions of India's Foreign Policy" organized by the National Maritime Foundation at India Habitat Centre*, New Delhi. <http://meaindia.nic.in/mystart.php?id=530117885>
24. Zhang, Dong (2006, September), India looks East: Strategies and Impacts, *Ausaid Working Paper*, p.17.
25. Subbarao, Duvvuri (2009, February), Impact of the

Global Financial Crisis on India Collateral Damage and Response, Speech delivered at the Symposium on *“The Global Economic Crisis and Challenges for the Asian Economy in a Changing World”* organized by the Institute for International Monetary Affairs, Tokyo. http://www.rbi.org.in/scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=410

26. Asia-Pacific economies are mentioned, including Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Taiwan, China mainland, Hong Kong, Macao, Japan, South Korea, North Korea, Mongolia, Australia, Fiji, Nauru, New Zealand, Papua New Guinea, Solomon, Tonga, Vanuatu, and Samoa.
27. Calculating from data of Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry, Government of India), India Export-Import Data Bank: Version 6.0 - Tradestat, http://commerce.nic.in/eidb/_default.asp
28. Rao, Narasimha P.V., op.cit. p.16.
29. Sikri, Rajiv, op.cit. p.21.
30. Narayana, Vemuni Lakshmi and Babu, S. Dhinesh,

India's Economic Growth and the Role of Foreign Direct Investment, http://www.indianmba.com/Faculty_Column/FC819/fc819.html

31. Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry, India), *Fact Sheet on Foreign Direct Investment (FDI) From August 1991 to September 2005*, p.6.
32. Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry, India), *Fact Sheet on Foreign Direct Investment (FDI) From August 1991 to October 2010*, pp.5-7.
33. *List of countries by GDP (nominal)*. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29 accessed April 27, 2012.
34. Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry, India), *Fact Sheet on Foreign Direct Investment (FDI) from April 2000 to December 2008*, p.6.
35. North Eastern Council Secretariat, *Annual Plan 2007-2008 North Eastern Council*, p.5.

36. North Eastern Council Secretariat, op.cit., p.41.
37. North Eastern Council Secretariat, op.cit., p.8.
38. Singh, Manmohan (2005, December) Keynote Address at *Special Leader's Dialogue of ASEAN Business Advisory Council*, Kuala Lumpur. <http://www.indianembassy.org/prdetail1003/--keynote-address-by-prime-minister-dr.-manmohan-singh-at-special-leader's-dialogue-of-asean-business-advisory-council->
39. Mukherjee, Pranab (2006, November) Speech at the 46th National Defence College Course, *Indian Foreign Policy: A Road Map for the Decade Ahead*. <http://meaindia.nic.in/mystart.php?id=530111969>
40. The criteria applied for a country to become a member of EAS: (1) a Dialogue Partner of ASEAN; (2) ratification of Treaty of Amity and Cooperation (TAC) in Southeast Asia; and (3) substantial relations with ASEAN.
41. Chaulia, Sreeram S. (2002), BJP, India's Foreign Policy and the "Realist Alternative" to the Nehruvian Tradition, *International Politics* 39, p. 223.

42. *Report on Round Table Conference on India-ASEAN Relation*, (2009 March), <http://www.maritimeindia.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=169>
43. Ministry of Foreign Affairs (Government of India), *India-Myanmar Relations*, December 2011. <http://www.mea.gov.in/meaxpsite/foreignrelation/myanmar.pdf>
44. Ministry of Foreign Affairs (Government of India), *India-Cambodia Relations*, January 2012. <http://www.mea.gov.in/meaxpsite/foreignrelation/cambodia.pdf>
45. Ministry of Foreign Affairs (Government of India), *India-Cambodia Relations*, August 2011. <http://www.mea.gov.in/meaxpsite/foreignrelation/laopdr.pdf>
46. Shekhar, Vibhanshu (2012), Two Decades of India's Look East Policy, in Jha, Ganganath and Shekhar, Vibhanshu (Eds)., *Rising India in the Changing Asia-Pacific: Strategies and Challenges*, New Delhi: Pentagon Press, p.17.

47. Press Information Bureau (Government of India), India signs four economic agreements with Myanmar, *Press Release*, June 24, 2008, <http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=39761>
48. See Shekhar, Vibhanshu, op.cit., p.17.
49. Singh, Manmohan (2004, July), speech at the Inaugural BIMST-EC Summit. <http://meaindia.nic.in/mystart.php?id=53018146>
50. Singh, Manmohan (2011, November), statement at the 9th ASEAN- India Summit. <http://meaindia.nic.in/mystart.php?id=530118540>
51. Ghoshal, Baladas (2009), India's Look-East Policy and Vietnam, *Mainstream*, Vol XLVII, No.40. <http://www.mainstreamweekly.net/article1639.html>
52. Patasani, P.K. (2010), India and Its Look East Policy, *Nam Today*, Vol. XXVII, No.04, p.21.
53. Patasani, P.K. (2010), op.cit., p.20.
54. Rao, Narasimha P.V., op.cit., p.10.
55. Shear, David B. (2011, September) Press Conference at the Rose Garden. <http://vietnam.usembassy.gov/ambremarks->

090911.html

56. Obama, Barack (2010, November), in his remarks to Members of both Houses of Parliament of India, *“Like your neighbours in Southeast Asia, we want India not only to “look East,” we want India to “engage East” because it will increase the security and prosperity of all our nations”*. See Remarks by President Mr. Barack Obama to Members of both Houses of Parliament in the Central Hall. <http://meaindia.nic.in/mystart.php?id=530116636>
57. Resolution of the Seventh Congress: Adoption of Sixth Party Central Committee’s Political Report at the Seventh Congress, 27 June 1991 (in Vietnamese).
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=8&leader_topic=224&id=BT2440658679, accessed 6 April 2012.
58. Political Report of the Seventh Central Committee at the Eight Congress, 1996 (in Vietnamese).
<http://123.30.190.43:8080/tiengviet/>

[tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191
&subtopic
=8&leader_topic=225&id=BT2540633010](http://tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=8&leader_topic=225&id=BT2540633010), accessed 6
April 2012.

59. Political Report of the Eighth Central Committee at the Ninth Congress, 2001 (in Vietnamese).http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=8&leader_topic=226&id=BT251105_30192, accessed 6 April 2012.
60. Vietnam luôn coi An Do là đối tác chiến lược (Vietnam always treats India as a strategic partner), *People's Army Newspaper Online*, February 2010. <http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/104529/Default.aspx> (Vietnamese), accessed 10 April 2012.
61. Prasannarajan, S. (2000, November), Ahoy Hanoi, *India Today on the net*.<http://www.india-today.com/itoday/20001120/diplomacy6.shtml>
62. Joint Declaration on the Framework of Comprehensive Cooperation between the Republic of India and the Socialist Republic of Vietnam as They Enter the 21st Century, New Delhi - May 01, 2003, [http:// meaindia.nic.in/](http://meaindia.nic.in/)
63. See *Vietnam - India joint declaration on strategic*

partnership,

<http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr040807105001/ns070709164916#lhrFZb14XT4F>

64. *VN, India hold second strategic dialogue*, 09/08/2011.
<http://news.gov.vn/Home/VN-India-hold-second-strategic-dialogue/20118/11290>. vgp
65. Nanda, Prakash, op.cit., p.389.
66. Ministry of Foreign Affairs (Government of India), Annual Report 2009-2010, p.26.
67. *Deccan Chronicle* (2011 June), India set to drop anchor off China.
<http://www.deccanchronicle.com/channels/nation/north/india-set-drop-anchor-china-764>
68. Ministry of Foreign Affairs of India, Incident involving INS Airavat in South China Sea, *Press Briefings*, September 01, 2011, <http://meaindia.nic.in/mystart.php?id=530318137>
69. *Hindustan Times* (2011 September), Beijing says keep off South China Sea, Delhi unmoved.
<http://www.hindustantimes.com/Beijing-says->

[keep-off-South-China-Sea-Delhi-unmoved/H1-Article1-746246.aspx](#)

70. *VN, India hold second strategic dialogue*, 09/08/2011, <http://news.gov.vn/Home/VN-India-hold-second-strategic-dialogue/20118/11290.vgp>
71. Ministry of Foreign Affairs of India, op.cit.
72. *Hindustan Times* (2011 September), China objects to oil hunt, India says back off. <http://www.hindustantimes.com/China-objects-to-oil-hunt-India-says-back-off/H1-Article1-745854.aspx>
73. *The Times of India* (2011 September), Undeterred India to hunt for oil in South China Sea. <http://timesofindia.indiatimes.com/india/Undeterred-India-to-hunt-for-oil-in-South-China-Sea/articleshow/10012959.cms>
74. *The Economic Times* (2011 September), China may assert itself but India will protect its rights: Minister of State for Defence M M Pallam Raju. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-09-16/news/30165250_1_incursions-south-china-sea-india-and-china

75. *The Times of India* (2011 September), Undeterred India to hunt for oil in South China Sea. <http://timesofindia.indiatimes.com/india/Undeterred-India-to-hunt-for-oil-in-South-China-Sea/articleshow/10012959.cms>
76. Results calculated from data of Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry, India), *Export Import Data Bank Version 6.0 - Tradestat*, <http://commerce.nic.in/eidb/default.asp>
77. Calculating from General Statistics Office of Vietnam, *Statistical Yearbook of Vietnam 2002* (pp.372&374).
78. Calculating from General Statistics Office of Vietnam, *Statistical Yearbook of Vietnam 2010* (pp.522&529).
79. Calculating from General Statistics Office of Vietnam, *Statistical Yearbook of Vietnam 2002* (p.524), *Statistical Yearbook of Vietnam 2005* (pp.426-435) and *Statistical Yearbook of Vietnam 2010* (pp.522- 531).

80. Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry, India), *Factsheet on Foreign Direct Investment, from August 1991 to April 2011*, p.7. See http://dipp.nic.in/fdi_statistics/india_fdi_index.htm
81. Foreign Investment Agency (Ministry of Planning and Investment, Vietnam), [http://ia.mpi.gov.vn/News.aspx?ctl=newsdetail&p=3.26 &aID=1062](http://ia.mpi.gov.vn/News.aspx?ctl=newsdetail&p=3.26&aID=1062)
82. Ibid.
83. Ministry of Foreign Affairs (Government of Vietnam), <http://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040807105039/ns070705102310/view#iJrqC1zHwX8R> (in Vietnamese).
84. Ministry of Foreign Affairs, Vietnam, *Vietnam-India Relations*, December 2009, http://www.mofa.gov.vn/en/cn_vakv/ca_tbd/nr040819102240/ns050131105108#zT5xVHViXywc
85. Satyanand, Premila Nazareth and Raghavendran, Pramila (2010 September), *Outward FDI from India and its policy context*, Vale Columbia Center on

Sustainable International Investment, p.13.

86. IAI Work Plan, Narrowing the Development Gap within ASEAN: Assisting New Member Countries (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam), July 2002 - June 2008, <http://www.asean.org/14237.htm>
87. *Joint Statement of the First ASEAN-India Summit*, Phnom Penh, 5 November 2002, <http://www.asean.org/13198.htm>
88. Singh, Manmohan (2005, December) announcing proposals at the 4th India-ASEAN Summit. <http://meaindia.nic.in/mystart.php?id=530110470>
89. *Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework and IAI Work Plan 2 (2009-2015)*, p.10, <http://www.asean.org/22325.pdf>
90. Sakhuja, Vijay (2012), Strategic Dimensions of India's Look East Policy, in Ram, Amar Nath (Ed.), *Two Decades of India's Look East Policy*, Manohar, p.225.
91. While meeting the ASEAN journalists covering Delhi Dialogue IV, Minister S.M. Krishna said that "Nobody can own a particular sea, there are international conventions. They demarcate certain

maritime boundaries. Beyond that, international conventions come into operation". See India tells Asean it believes in 'open' South China Sea, *The Malaysia Reserve*, 15 February 2012. http://themalaysianreserve.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1251:india-tells-asean-it-believes-in-open-south-china-sea&catid=36:corporate-malaysia&Itemid=120

92. *Bloomberg* (2012 February), Russia to Help Vietnam Produce Anti- Ship Missiles, RIA Says. <http://www.bloomberg.com/news/2012-02-16/russia-to-help-vietnam-produce-anti-ship-missiles-ria-says-1-.html>
93. Ministry of External Affairs (Government of India), *Weekly Economic Bulletin*, Issue No. 220, July 03- July 09, 2007, p.4. http://www.indiacgny.org/economic_bulletin_ile/File19.pdf
94. *Rediff Business* (2009 August), Farmer's body slams signing of FTA with ASEAN. <http://business.rediff.com/report/2009/aug/15/kisan-sabha-slams-asean-fta-deal.htm>

95. *The Economic Times* (2009 July), Mentioning of ASEAN-India FTA in goods, Indian Prime Minister Manmohan Singh stated: "A free trade agreement with the ASEAN is an international political commitment and is also part of the 'Look-East' policy". See, No takers for Antony's opposition to Indo-Asean FTA, <http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/4818189.cms>.

REFERENCES

- Acharya, Alka (2007 June), paper for Commemorative Seminar to mark the 35th Anniversary of the Establishment of Full Diplomatic Relations between India and Vietnam, Hanoi, *India's Look East Policy: Regional Strategy or A Rising Power*.
- Chaulia, Sreeram S. (2002), BJP, India's Foreign Policy and the "Realist Alternative" to the Nehruvian Tradition, *International Politics* 39.
- Devare, Sudhir (2006), *India & Southeast Asia: Towards Security Convergence*, ISEAS, Singapore.
- Ghoshal, Baladas (1996) (ed.), *India and Southeast Asia: Challenges and Opportunities*, Konark Publishers Pvt Ltd & India International Centre.
- Ghoshal, Baladas (2009), India's Look-East Policy and Vietnam, *Mainstream*, Vol. XLVII, No 40.
- IAI Work Plan, Narrowing the Development Gap within ASEAN: Assisting New Member Countries (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam), July 2002 - June 2008.*

Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework and IAI Work Plan 2 (2009-2015).

Jha, Ganganath and Shekhar, Vibhanshu (eds.) (2012), *Rising India in the Changing Asia-Pacific: Strategies and Challenges*, Pentagon Press.

Kapur, Pradeep Kumar (2007 June), *India's Engagement with East Asia*, paper for Commemorative Seminar to mark the 35th Anniversary of the Establishment of Full Diplomatic Relations between India and Vietnam, Hanoi.

Kesavan, K.V. (ed.), *Building a Global Partnership: Fifty Years of Indo- Japanese Relations*, Lancer Books.

Ladwig, Walter C.III (2010), *India and the Balance of Power in the Asia-Pacific*, JFQ, Issue 57, 2nd quarter.

Ministry of External Affairs (Government of India), *Annual Report 1995- 1996*.

- Ministry of External Affairs (Government of India),
Annual Report 2006- 2007.
- Ministry of External Affairs (Government of India),
Weekly Economic Bulletin, Issue No. 220, July 03-
July 09, 2007.
- Ministry of Foreign Affairs (Government of India), *Annual
Report 2009- 2010.*
- Nanda, Prakash (2003), *Rediscovering Asia - Evolution
of India's Look East Policy*, Lancer Publishers &
Distributors.
- Narasimha Rao, P.V. (1994), *India and the Asia-Paciic:
Forging a New
Relationship*, ISEAS, Singapore.
- North Eastern Council Secretariat, *Annual Plan 2007-
2008 North Eastern Council.*
- Patasani, P.K. (2010), India and Its Look East Policy,
NAM Today, Vol.
XXVII, No. 04.
- Ram, Amar Nath (2012) (ed.), *Two Decades of India's
Look East Policy: Partnership for Peace, Progress and
Prosperity*. Manohar.

Satyanand, Premila Nazareth and Raghavendran, Pramila (2010 September), *Outward FDI from India and its policy context*, Vale Columbia Center on Sustainable International Investment.

Sikri, Rajiv (2007 September), India's Foreign Policy Priorities in the Coming Decade, *ISAS Working Paper*, No. 25.

Zhang, Dong (September 2006), India looks east: Strategies and impacts, *Ausaid Working Paper*.

लेखक के बारे में



डॉ. जो जुआन यिन्ह इंस्टीट्यूट फार साउथईस्ट एशियन स्टडीज (आईएसईएस), वियतनाम अकैडमी ऑफ सोशियल साइंसेस (वीएसएस), हनोई में रिसर्च फेलो है। उन्होंने वियतनाम ग्रेजुएट अकैडमी ऑफ सोशियल साइंसेस, वियतनाम से अपनी पीएच.डी “दि रोल ऑफ आसियान इन इंडियाज लुक ईस्ट पालिसी ” विषय में पूरी की है।

उन्होंने भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी, आसियान सामुदायिक भवन की प्रक्रिया, एशिया-प्रशांत क्षेत्र की विदेश नीति और सुरक्षा के मुद्दों और थाईलैंड में नागरिक समाज, थाईलैंड और फिलीपींस की राजनीति पर शोध किया है। उनकी रुचि के क्षेत्रों में भारत-आसियान संबंध, दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक एकीकरण और सुरक्षा, एशिया-प्रशांत में क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकला शामिल हैं। उन्होंने वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने वियतनाम और भारत दोनों पत्रिकाओं में लेखों में भी योगदान दिया है। उनका वर्तमान अनुसंधान फोकस आसियान सामुदायिक निर्माण की प्रक्रिया, एशिया-प्रशांत के साथ भारत की साझेदारी और म्यांमार में वर्तमान बदलावों पर है।

(अस्वीकरण: *डॉ. जो जुआन यिन्ह ने फरवरी-मार्च 2012 के दौरान डॉ. यिकाश रंजन के पर्यवेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद में रिसर्च इंटर्न के तौर पर कार्य किया है। ये लेखक के व्यक्तिगत मत हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद के विचारों को व्यक्त नहीं करता है।)

a



अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड़, नई दिल्ली-110001